DD

RNI No. DLHIN/25/A2321

दिल्ली से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र

दिव्य दिल्ली

वर्ष: 01, अंक: 20, पृष्ठ: 08

infodivyadelhi@gmail.com

रविवार, 28 सितम्बर, 2025 तदनुसार 19 भाद्रपद विक्रमी सम्वत 2082 | www.divyadelhi.com | facebook.com/divyadelhi

तापमान अधिकतम 30 डिग्री न्यूनतम 25 डिग्री

सूयोदय 05.25 | सूर्यास्त 06.50

हालात संभालने में पूरी तरह असफल रहे पीएम मोदी और शाह

लेह

लद्दाख में बिगड़ते हालात को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने हालात को काबू में करने के बजाय और बिगड़ने दिया है। तिवारी ने कहा कि गिरफ्तारियां समस्या का समाधान नहीं हैं, बल्कि केंद्र को अपने वादों को पूरा करना होगा। प्रमोद तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने राज्य का दर्जा बहाल करने और जम्मू-कश्मीर के साथ लद्दाख को भी समान अधिकार देने का वादा किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि इन वादों को पूरा करने के बजाय सरकार दमनकारी रवैया अपना रही है। तिवारी ने कहा कि मणिपुर को पिछले दो साल से संभाल नहीं पाए और अब लद्दाख में हालात हाथ से निकल गए।

संसद की स्थायी समितियों का कार्यकाल दो साल करने पर विचार

नई दिल्ली

केंद्र सरकार संसद की स्थायी समितियों का कार्यकाल बढ़ाकर दो साल करने पर विचार कर रही है। वर्तमान में इन समितियों का कार्यकाल केवल एक साल का होता है। सांसदों ने सरकार से शिकायत की थी कि इतने कम समय में किसी विषय पर ठोस और सार्थक काम करना संभव नहीं है। सरकार इस पर जल्द ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति सी. पी. राधाकृष्णन से चर्चा करने के बाद फैसला ले सकती है। जानकारी के मुताबिक, कुछ सांसदों का कहना है कि एक साल की अवधि में समितियां चुने गए विषयों पर पूरी तरह काम नहीं कर पातीं। ऐसे में कार्यकाल दो साल होने से वे गहराई से अध्ययन कर सिफारिशें दे सकेंगी। इस मांग के बाद सरकार ने गंभीरता से विचार शुरू किया है। आमतौर पर स्थायी समितियों का नया कार्यकाल सितंबर के अंत या अक्तूबर की शुरूआत में तय होता है।

मौलाना भूल गया था कि यूपी में सरकार किसकी है: सीएम योगी

मौलाना धमकी देकर जाम लगाने की बात करता था, लेकिन हमने कहा कि न जाम होगा, न कर्फ्यू लगेगा: सीएम

लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली की घटना पर कहा- "बरेली में एक मौलाना भूल गया था कि शासन किसका है। वह धमकी देकर जाम लगाने की बात करता था, लेकिन हमने कहा कि न जाम होगा, न कर्फ्यू लगेगा। हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी दंगा करना भूल जाएंगी।" योगी आदित्यनाथ ने जोर देकर कहा कि 2017 के बाद उनकी सरकार ने दंगाइयों को चुन-चुनकर सजा दी और ऐसी भाषा में जवाब दिया, जो वे समझते थे। इस सख्ती ने उत्तर प्रदेश में शांति और सुरक्षा का नया युग स्थापित किया, जिससे यूपी की ग्रोथ स्टोरी की शुरूआत हुई।

चाचा-भतीजा और माफिया राज पर करारा प्रहार

योगी ने पूर्ववर्ती सरकारों पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि 'चाचा-भतीजा' वसूली के धंधे में लिप्त थे और हर जिले में एक माफिया को समानांतर सत्ता चलाने की छूट दी गई थी। उन्होंने कटाक्ष किया कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग माफियाओं के सामने नतमस्तक थे। सत्ता के मुखिया माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाकर गौरवान्वित महसूस करते थे। योगी ने कहा कि ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था में न बेटियां सुरक्षित थीं, न व्यापारी, और न ही किसान। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब सत्ता बेइमान और भ्रष्ट लोगों के हाथ में आती है, तो वह समाज को जाति और परिवार के नाम पर गुमराह करती है।

ऐसे लोगों के लिए हमने बुलडोजर बनाया है।" उनकी सरकार ने माफिया राज को जड़ से उखाड़कर प्रदेश को विकास की राह पर ला खड़ा किया।

यूपी रेवेन्यू सरप्लस वाला स्टेट बना

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को राजधानी में एक प्रतिष्ठित मीडिया समूह द्वारा आयोजित 'विकसित उत्तर प्रदेश विजन @ 2047' कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए '8 ईयर्स ऑफ यूपी गवर्नमेंट' पुस्तक का विमोचन किया और प्रदेश की प्रगति की कहानी को दमदारी से प्रस्तुत किया। उन्होंने पिछले साढ़े आठ वर्षों में उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा की चर्चा करते हुए परिवारवाद, जातिवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को उजागर किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी उन लोगों के लिए अविश्वसनीय है, जो पौरुष की कमी और अपने पुरुषार्थ को करने से डरते थे। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अवसर तो मिला, लेकिन उन्होंने इसे परिवारवाद, लूट-खसोट और अराजकता का जरिया बना लिया।

यूपी को बीमारू राज्य से बाहर निकाला

सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमने ईश्वर और अपने पुरुषार्थ पर विश्वास के साथ उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से बाहर निकाला। आज यह ग्रोथ स्टोरी उस कहानी को आपके सामने लाएगी। सीएजी की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश 2023 में 37 हजार करोड़ रुपये के राजस्व अधिशेष (रेवेन्यू सरप्लस) वाला राज्य था और वर्तमान में यह बढ़कर 70 हजार करोड़ रुपये हो गया है। इतनी बड़ी आबादी वाला राज्य बिना किसी रुकावट के अपने सभी विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति ने यूपी के विकास को बाधित किया था। दंगों की आग में व्यापार को बर्बाद किया गया और भ्रष्ट व्यवस्था ने नौकरशाही को अपंग बना दिया था।

सोनम वांगचुक पर पाकिस्तानी कनेक्शन और विदेशी फंडिंग का शक... जांच जारी

लेह

लद्दाख के पुलिस महानिदेशक एस. डी. सिंह जामवाल ने शनिवार को बताया कि सोनम वांगचुक के खिलाफ पाकिस्तान से कथित संबंधों को लेकर जांच जारी है। यह जांच पिछले महीने एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंट की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुई है, जो वांगचुक के विरोध प्रदर्शनों के वीडियो सीमा पार भेज रहा था। डीजीपी जामवाल ने सोनम वांगचुक को बुधवार को हुई हिंसा का मुख्य सूत्रधार बताया, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और कई

अन्य घायल हुए। शुक्रवार को वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लेकर राजस्थान के जोधपुर जेल भेज दिया गया।

उनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं

डीजीपी ने कहा अब तक जांच में जो सामने आया है, उसे फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। लेकिन वांगचुक के भाषणों और गतिविधियों से यह साफ है कि उनकी मंशा लोगों को भड़काने की थी। उन्होंने ह्यअरब स्प्रिंगह्ण और नेपाल, बांग्लादेश व श्रीलंका में हुए आंदोलनों का जिक्र कर लोगों को उकसाया। उन्होंने बताया कि विदेशी फंडिंग और एफसीआरए उल्लंघन की भी जांच की जा रही है। एक पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटिव को पकड़ा गया है, जो वांगचुक के नेतृत्व वाले प्रदर्शनों के वीडियो पाकिस्तान भेज रहा था।

1.29 करोड़ के सोने के बिस्कुट के साथ तस्कर गिरफ्तार

कोलकाता

भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तैनात बीएसएफ दक्षिण बंगाल सीमांत (उत्तर 24 परगना जिला) की 143वीं वाहिनी के सतर्क जवानों ने एक बड़ी तस्करी की कोशिश नाकाम कर दी। सीमा चौकी तराली-1 पर खुफिया जानकारी के आधार पर की गई कार्रवाई में जवानों ने एक तस्कर को रंगेहाथ पकड़ लिया। उसके पास से 20 सोने के बिस्कुट बरामद हुए, जिनका कुल वजन 1116.27 ग्राम है। जब्त किए गए सोने की अनुमानित कीमत लगभग 1.29 करोड़ आंकी गई है। तराली-1 सीमाचौकी क्षेत्र के अंतर्गत हाकिमपुर चेक पोस्ट पर मिली। क्षेत्र से सोने की तस्करी की कोशिश की जाएगी।

यह भारत माता के प्रति भक्ति, प्रेम और समर्पण: भागवत

प्रार्थना मातृभूमि के प्रति भक्ति प्रेम और समर्पण की अभिव्यक्ति है: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख

नई दिल्ली

ने शनिवार को कहा कि संगठन की प्रार्थना भारत माता की वंदना और देश एवं ईश्वर के प्रति स्वयंसेवकों का सामूहिक संकल्प है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत संकल्प प्रत्येक स्वयंसेवक के दृष्टिकोण में होते हैं, लेकिन साझा मिशन और मूल्य संघ की प्रार्थना से ही उत्पन्न होते हैं, जिसका 1940 से स्वयंसेवकों द्वारा प्रतिदिन पाठ किया जाता रहा है। प्रार्थना की भावना संकल्प की शक्ति है और यह मातृभूमि के प्रति भक्ति, प्रेम और समर्पण की अभिव्यक्ति है।

आरएसएस की प्रार्थना मातृभूमि के प्रति समर्पण का सामूहिक संकल्प

संघ प्रार्थना की ऑडियो रिकॉर्डिंग की जारी

नागपुर के रेशिमबाग स्थित महर्षि व्यास सभागार में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भागवत ने प्रसिद्ध गायक शंकर महादेवन द्वारा गाई गई संघ प्रार्थना की ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की। अभिनेता सचिन खेडेकर, जाने-माने वॉयस-ओवर आर्टिस्ट व एंकर हरीश भिमानी और संगीतकार राहुल रानाडे भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

लंदन के स्टूडियो के साथ रिकॉर्ड किया गया गाना

यह गीत लंदन के एक स्टूडियो में रॉयल फिलहारमोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ रिकार्ड किया गया था, जिसमें सभी विदेशी संगीतकार थे। महादेवन ने संगीतमय प्रस्तुति में अपनी आवाज दी, जबकि मराठी में खेडेकर ने और हिंदी में भीमानी ने वॉयस-ओवर के रूप में अपना स्वर दिया। आठ अलग-अलग भाषाओं में स्वर दिए गए। उल्लेखनीय है कि संघ की मूल प्रार्थना नरहरि नारायण भिड़े द्वारा रचित थी और यह पहली बार 23 अप्रैल, 1940 को पुणे में संघ शिक्षा वर्ग में यादव राव जोशी द्वारा गाई गई थी। प्रार्थना का प्रारंभिक प्रारूप 1939 में पुणे में एक बैठक के दौरान तैयार किया गया था।

भागवत ने कहा, "यह प्रार्थना एक भावना है जो स्वयंसेवकों को मातृभूमि के प्रति भक्ति, प्रेम और समर्पण के सामूहिक संकल्प में मदद करती है। यह प्रार्थना है कि हम देश को क्या दे सकते हैं और फिर ईश्वर से प्रार्थना है कि वह हमें देश की सेवा करने में मदद करें।"

उन्होंने कहा कि ऑडियो जारी होने के साथ ही यह प्रार्थना ज्यादा से

आई लव मोहम्मद विवाद: कर्नाटक में आठ गिरफ्तार

नई दिल्ली

कर्नाटक पुलिस ने दावणगेरे में आई लव मोहम्मद विवाद और उससे जुड़ी हिंसा मामले में शनिवार को आठ लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि क्षेत्र में शांति और कानून-व्यवस्था भंग करने वाले और लोगों को पकड़ने और गिरफ्तार करने के लिए चार विशेष टीमें बनाई गई हैं।

यह कार्रवाई 24 सितंबर को कार्ल मा?र्क्स नगर इलाके में एक बैनर विवाद को लेकर दो समुदायों के बीच झड़प के बाद की गई है। घटना के दौरान हिंदुओं के घरों पर पथराव किए जाने के आरोप लगे

थे। इस सिलसिले में 100 लोगों के खिलाफ तीन प्राथमिकी दर्ज की गई और दोनों पक्षों के आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया।

अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

पुलिस इंटरनेट मीडिया पर भी नजर रख रही है। दावणगेरे जिले की एसपी उमा प्रशांत ने चेतावनी दी है

हरी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 100 दिवसीय पहल, 300 शहरों के लोग बताएंगे अनुभव

नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने शहरी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 100 दिवसीय पहल की है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने स्वच्छ शहर जोड़ी (एसएसजे) कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत 72 शहरों और लगभग 200 नए शहरों का मूल्यांकन किया जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में शहरों के हालिया प्रदर्शन के आधार पर, शीर्ष प्रदर्शन करने वाले शहरों की पहचान संरक्षक शहरों के रूप में की गई है और उन्हें कम प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षु शहरों के साथ

जोड़ा गया है। स्वच्छ भारत मिशन - शहरी (एसबीएम-यू) के तहत एसएसजे पहल की शुरूआत केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आवासन और शहरी कार्य राज्यमंत्री तोखन साहू, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विभिन्न राज्यों के शहरी विकास मंत्री, महापौर, आयुक्त, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव एस. कटिकिथला की उपस्थिति में की। एसएसजे पहल शहरी अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में सबसे बड़े समयबद्ध और व्यवस्थित परामर्श ढांचे में से एक है। इसका उद्देश्य ज्ञान एवं अनुभवों को साझा करना, सहकर्मी द्वारा शिक्षण और शहरी भारत में स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को बदलना है।

छोटे परमाणु रिएक्टर की रेस में तेजी से आगे बढ़ रहा भारत

नई दिल्ली

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और मशीन लर्निंग उद्योगों में जैसे-जैसे क्रांति ला रहे हैं, विश्वसनीय, स्वच्छ और स्केलेबल ऊर्जा की मांग बढ़ती जा रही है। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों बनने लगे हैं। कॉम्पैक्ट न्यूक्लियर पावर यूनिट अब ग्लोबल एनर्जी के क्षेत्र में पसंदीदा बनते जा रहे हैं। एसएमआर, दूर दराज द्वीपों को बिजली देने से लेकर डेटा सेंटर्स को ईंधन देने तक का काम करते है, जिसे परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अगली बड़ी चीज के रूप में देखा जा रहा है। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों को भारत सिर्फ किनारे से देख ही नहीं रहा है, बल्कि अपना खुद का निर्माण भी कर रहा है, भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर। आज, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर दुनिया के लिए चर्चा का विषय हैं और चीन के लिए गर्व की बात हैं।

समझिए क्या है एसएमआर?

एक विशेष बातचीत में, रूस के सरकारी परमाणु निगम रोसाटॉम में प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉ एलेक्जेंडर वोल्गिन ने एसएमआर की संभावनाओं और इस परिवर्तनकारी तकनीक पर भारत के साथ सहयोग करने के रूस के खुलेपन के बारे में बात की। डॉ. वोल्गिन ने बताया, "जब हम एसएमआर की बात करते हैं, तो हम छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों की बात कर रहे होते हैं। 'छोटे' का मतलब है कि वे पारंपरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की तुलना में कम जगह घेरते हैं, और 'मॉड्यूलर' का मतलब है कि वे कारखाने में इकट्ठे होते हैं और एक ही टुकड़े के रूप में ले जाए जा सकते हैं।" तमिलनाडु के कुडनकुलम जैसे विशाल परमाणु प्रतिष्ठानों के विपरीत, रूसी एसएमआर केवल 15-17 हेक्टेयर क्षेत्र में समा सकते हैं।

ये जुबीन का असम है, नेपाल नहीं बनने देंगे: सीएम हिमंता की सख्त टिप्पणी

महंत के बैंक खाते और क्रेडिट कार्ड फ्रीज कर दिए गए

सिंगापुर से गर्ग की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगवाने की प्रक्रिया चालू

नई दिल्ली

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा कि गायक जुबीन गर्ग की मौत के मामले में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंत और उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किए गए हैं। फेसबुक लाइव में सरमा ने कहा कि दोनों को 6 अक्टूबर को गुवाहाटी आकर अपना बयान देना होगा, अन्यथा पुलिस उनकी तलाश में अभियान तेज कर देगी। उन्होंने कहा, "चूंकि दुर्गा पूजा उत्सव शुरू हो रहा है, हम नहीं चाहते कि वे अभी आएं। लेकिन दशमी के बाद उन्हें आना ही होगा। उन्हें 6 अक्टूबर को गुवाहाटी आकर अपना बयान दर्ज कराना होगा।"

'सीआईडी के सामने पेश नहीं होना है तो अदालत जाओ'

मुख्यमंत्री ने कहा, 'अगर वे सीआईडी के समक्ष पेश नहीं होना चाहते हैं, जो 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में डूबने से गर्ग की मौत की घटनाओं की जांच कर रही है तो वे अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।'

मामले की जांच को लेकर सीएम सरमा ने दी जानकारी

उन्होंने आगे कहा कि महंत के बैंक खाते और क्रेडिट कार्ड फ्रीज कर दिए गए हैं ताकि वह ज्यादा देर तक बाहर न रह सकें। सरमा ने कहा कि सरकार सिंगापुर से गर्ग की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगवाने की प्रक्रिया में है और गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में किए गए दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पुलिस जांच में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यरत न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग गठित करने के लिए शुक्रवार को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है।

अमित शाह से कही बड़ी बात

उन्होंने आगे कहा, "मैंने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कहा है कि जिस दिन ऐसा लगेगा कि असम पुलिस जुबीन को न्याय नहीं दिला पाएगी, हम मामला सीबीआई को सौंप देंगे।" सरमा ने लोगों से संयम बरतने और "जुबीन के नाम पर असम को नेपाल बनाने की कोशिश में सरकार विरोधी राजनीति" में शामिल न होने का भी आग्रह किया।

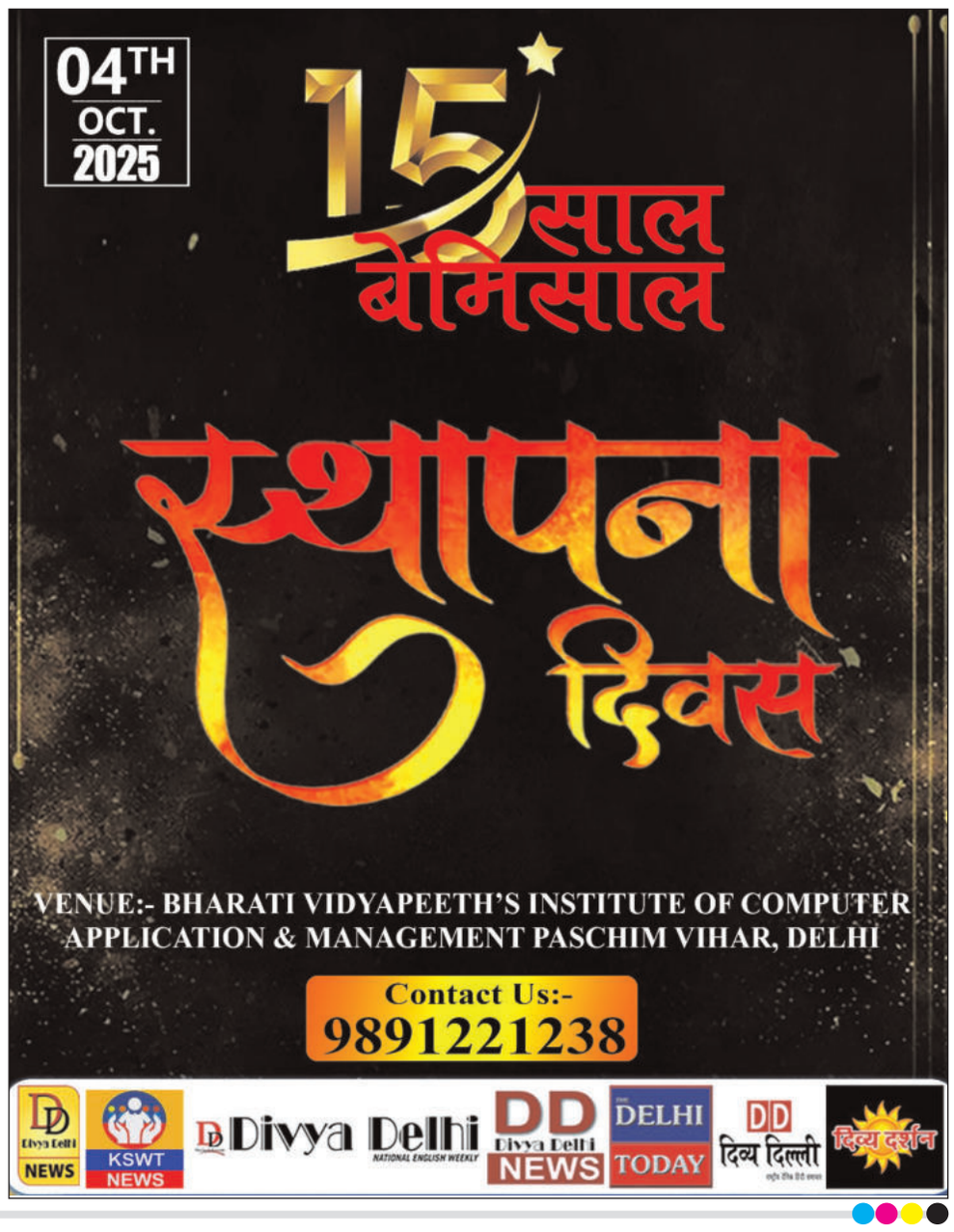

हमने देश को कांग्रेस के लूटतंत्र से बाहर निकाला: मोदी

भाजपा गरीबों की सेवा और उन्हें सशक्त बनाने वाली सरकार: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

ओडिशा से कर्नाटक तक भारी बारिश से मची तबाही, स्कूल बंद

नई दिल्ली

देश के कई राज्यों में लौटते मानसून के चलते हो रही भारी बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ओडिशा, मुंबई, तेलंगाना और कर्नाटक में भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में जलभराव से यातायात बाधित हो गया और लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन शनिवार सुबह करीब 4:30 बजे ओडिशा के गंजाम जिले में गोपालपुर तट से टकराया, जिससे राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार यह धीरे-धीरे पश्चिम की ओर बढ़ते हुए अगले 24 घंटों में कमजोर होगा।

पीएम मोदी का ओडिशा दौरा प्रभावित

बता दें कि ओडिशा में हो रही भारी बारिश के चलते पीएम नरेंद्र मोदी का ओडिशा दौरा भी प्रभावित हुआ। पहले उनका जनसभा स्थल गंजाम जिले के बेरहामपुर में तय था, लेकिन भारी बारिश की आशंका के कारण कार्यक्रम को झारसुगुड़ा में स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि, झारसुगुड़ा में भी तेज हवाओं और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है।इसके साथ ही मौसम विभाग ने नबरंगपुर जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि कोरापुट, मलकानगिरी, रायगढ़ा, गजपति, गंजाम समेत अन्य जिलों में येलो अलर्ट है। मछुआरों को 27 सितंबर दोपहर तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।

मुंबई में भारी बारिश का असर, यातायात प्रभावित

मुंबई और उपनगरों में शनिवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट देते हुए कहा है कि कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश हो सकती है। बीएमसी के अनुसार, मुंबई में बीते 24 घंटे में औसतन 30 मिमी बारिश हुई है। शहर में 2.25 बजे दोपहर को 3.48 मीटर की हाई टाइड और रात 8.17 बजे 1.06 मीटर की लो टाइड रहेगी। लोकल ट्रेनें कुछ देरी से चल रही हैं, लेकिन ट्रैफिक सामान्य है। लोग सावधानी बरतें और बिना जरूरत घर से बाहर न निकलें।

कर्नाटक के कालबुर्गी जिले में स्कूलों की छुट्टी

कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में भारी बारिश और मौसम विभाग की ऑरेंज अलर्ट चेतावनी के चलते स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है।

झारसुगुड़ा

ओडिशा के झारसुगुड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'डेढ़ साल पहले, विधानसभा चुनाव के दौरान, आप ओडिशावासियों ने एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया था। ये संकल्प था- 'विकसित ओडिशा'। आज हम देख रहे हैं कि ओडिशा डबल इंजन की रफ्तार से आगे बढ़ चला है। आज एक बार फिर, ओडिशा के विकास, देश के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम शुरू हुआ है। आज से, बीएसएनएल का एक नया अवतार भी सामने आया है। बीएसएनएल की स्वदेशी 4जी सेवाओं का शुभारंभ हो गया है।'

'भाजपा गरीबों की सेवा और उन्हें सशक्त बनाने वाली सरकार'

इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज शुरू की गई ब्रह्मपुर-उधना अमृत भारत ट्रेन से गुजरात के उड़िया लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'भाजपा सरकार गरीबों की सेवा और उन्हें सशक्त बनाने वाली सरकार है। हम गरीबों, दलितों, पिछड़े वर्गों और आदिवासियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर देते हैं... हमारी सरकार ने अब तक देश भर में 4 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराए हैं। ओडिशा में भी हजारों घरों के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है।'

प्रधानमंत्री का ध्यान हमेशा ओडिशा के विकास पर- मुख्यमंत्री माझी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'हमारा संकल्प है कि भारत चिप से लेकर जहाजों तक, हर चीज में आत्मनिर्भर बने... देश का हर नागरिक चाहता है कि हमारा देश अब किसी पर निर्भर न रहे, इसलिए पारादीप से झारसुगुड़ा तक एक विशाल औद्योगिक क्षेत्र बनाया जा रहा है। वहीं इस पहले ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान हमेशा ओडिशा के विकास पर रहा है... आपके मार्गदर्शन और निर्देशन में ओडिशा प्रगति के पथ पर अग्रसर है...ट्रेन, कौशल विकास परियोजनाएं, नया सेमीकंडक्टर पार्क आदि...।'

अंत्योदय गृह योजना के 50 हजार लाभार्थियों को सौगात

आठ राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। पीएम मोदी ने इस दौरान अंत्योदय गृह योजना के अंतर्गत 50,000 लाभार्थियों को स्वीकृति आदेश वितरित किए, जिसका उद्देश्य विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों और प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों सहित कमजोर परिवारों को पक्के मकान और वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

हमारा संकल्प है कि भारत हर चीज में आत्मनिर्भर बने- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'हमारा संकल्प है कि भारत चिप से लेकर जहाजों तक, हर चीज में आत्मनिर्भर बने... देश का हर नागरिक चाहता है कि हमारा देश अब किसी पर निर्भर न रहे, इसलिए पारादीप से झारसुगुड़ा तक एक विशाल औद्योगिक क्षेत्र बनाया जा रहा है... हमने देश में जहाज निर्माण के लिए 70 हजार करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी है, इससे भारत में 4.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश आएगा... इससे युवाओं को बहुत फायदा होगा, लाखों रोजगार पैदा होंगे।'

'देश में शिक्षा और कौशल विकास में अभूतपूर्व निवेश जारी'

हमारा संकल्प है कि भारत हर चीज में आत्मनिर्भर बने- पीएम मोदी

जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'आत्मनिर्भर भारत के लिए कुशल युवा और अनुसंधान का माहौल आवश्यक है... आज ओडिशा सहित पूरे देश में शिक्षा और कौशल विकास में अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है.।

कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी का करारा हमला

पीएम मोदी ने कहा कि आज मेरिट नाम से एक योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि हमारे युवाओं को अच्छी तकनीकी शिक्षा के लिए बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। देश के हर क्षेत्र और हर वर्ग के नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए आज बहुत काम किया जा रहा है।'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, '2014 में जब आपने हमें सेवा का अवसर दिया, तो हमने देश को इस कांग्रेस के लूटतंत्र से बाहर निकाला। अब भाजपा सरकार में दोगुनी बचत और दोगुनी कमाई का दौर आ गया है। जब कांग्रेस सत्ता में थी, तो हमारे कर्मचारियों, व्यापारियों और कारोबारियों को 2 लाख रुपये तक की वार्षिक कमाई पर भी आयकर देना पड़ता था, लेकिन आज उन्हें 12 लाख रुपये तक की वार्षिक कमाई पर एक रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ता है।'

प्रधानमंत्री का ध्यान हमेशा ओडिशा के विकास पर- माझी

वहीं इस पहले ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान हमेशा ओडिशा के विकास पर रहा है... आपके मार्गदर्शन और निर्देशन में ओडिशा प्रगति के पथ पर अग्रसर है... दुर्गा पूजा ओडिशा का एक बड़ा त्योहार है... आज कई परियोजनाएं शुरू होने जा रही हैं जैसे नई अमृत भारत ट्रेन, कौशल विकास परियोजनाएं, नया सेमीकंडक्टर पार्क आदि...।'

दिल्ली पुलिस भर्ती में ओबीसी आरक्षण की कमी, टैगोर ने शाह से मांगा जवाब

नई दिल्ली

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस भर्ती में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) के आरक्षित पदों में कमी को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता ने अपने पत्र में कहा कि सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार किसी भी भर्ती में 27% पद ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होने चाहिए।

दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए निकलीं भर्तियां

दिल्ली पुलिस कांस्टेबल (एक्जीक्यूटिव) भर्ती के तहत कुल 7,565 पद निकाले गए हैं। इसमें 27% आरक्षण के हिसाब से 2,043 पद ओबीसी को मिलने चाहिए थे, लेकिन भर्ती अधिसूचना में केवल 1,608 पद ही ओबीसी के लिए तय किए गए हैं। इस तरह 435 पदों की कमी है। उन्होंने इसे संवैधानिक प्रावधान और आरक्षण नीति का उल्लंघन बताया। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने आगे कहा कि यह मामला केवल संख्याओं का नहीं, बल्कि न्याय, समानता और लाखों ओबीसी युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। उन्होंने गृहमंत्री से तीन मुख्य सवालों के जवाब मांगे हैं।

20 नक्सलियों ने सीआरपीएफ दल पर हमला किया; गोला बारूद, स्कैनर व छर्रे हटाने के उपकरणों से लैस थे

नई दिल्ली

झारखंड में सुरक्षा बलों पर भाकपा (माओवादी) कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हमले से संबंधित 2024 के मामले में एक प्रमुख आरोपी के खिलाफ राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) ने आरोपपत्र दायर किया है। इसमें कई अहम बात कही गई हैं। करीब 20 नक्सलियों ने सीआरपीएफ दल पर उस वक्त घात लगाकर हमला किया था, जब वह टीम सर्च अभियान पर निकली थी। सुरक्षा बलों ने जब जवाबी कार्रवाई की तो नक्सली घने जंगल में भाग निकले। मौके से जो सामान बरामद हुआ, उसमें गोला बारूद, पेंसिल बैटरी, पोर्टेबल स्कैनर व छर्रे हटाने के उपकरण और एफएम रेडिया आदि बरामद हुए थे। बता दें कि बिहार के जमुई जिले के अभिजीत कोड़ा उर्फ सुनील कोड़ा उर्फ मतला कोड़ा उर्फ मतलू पर झारखंड के रांची स्थित एनआईए विशेष न्यायालय में दायर आरोपपत्र दायर किया गया है। इसमें भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1908 और यूए (पी) अधिनियम, 1967 की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। भाकपा (माओवादी) का एक सशस्त्र कार्यकर्ता, कोड़ा प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन की आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने और अपने अन्य नेताओं/कैडरों के साथ मिलकर संगठन को बढ़ावा देने/मजबूत करने की आपराधिक साजिश का हिस्सा था। एनआईए की जांच से पता चला कि वह वरिष्ठ माओवादी नेताओं के लिए कूरियर और संदेशवाहक के रूप में काम कर रहा था।

महाराष्ट्र में बारिश से किसान प्रभावित: उद्धव ने की पूरा कर्ज माफ करने की मांग

मुंबई

महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते किसानों को बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा है। कारण है कि बारिश के चलते फसलें बर्बाद हो गई। साथ ही नौ से ज्यादा किसानों की मौत हो गई। ऐसे में अब शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने किसानों के लिए पूरी कर्ज माफी की मांग की है। इतना ही नहीं उद्धव ने राज्य की फडणवीस सरकार से प्रभावित किसानों को 50000 रुपये प्रति हेक्टेयर राहत राशि देने के साथ-साथ किसानों की समस्याओं पर चर्चा के लिए विशेष विधान सभा सत्र बुलाने की भी मांग की है।

भाजपा सरकार पर साधा निशाना

इस दौरान उद्धव ने राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने फडणवीस सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार राज्य को सही तरीके से चला पाने में असमर्थ हैं।। बता दें कि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में 20 सितंबर से भारी बारिश और बढ़ती नदियों की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। सरकार के अनुसार, करीब 30,000 हेक्टेयर से अधिक फसलें बाढ़ में बह गई हैं और कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई।

सीएम फडणवीस ने की राहत पैकेज का एलान

ऐसे में गंभीर स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और किसानों की मदद के लिए तुरंत राहत पैकेज देने की अपील की। गौरतलब है कि मराठवाड़ा जैसे सूखे इलाके में इस बार भारी बारिश ने किसानों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। वहीं, दूसरी ओर शिव सेना (यूबीटी) और कांग्रेस ने किसानों के लिए तत्काल राहत की मांग को लेकर अलग-अलग प्रदर्शन करने का एलान किया है। दोनों विपक्षी दलों ने सरकार से राज्य में वेट ड्राउट यानी गीला सूखा घोषित करने की भी मांग की है ताकि किसानों को विशेष मदद दी जा सके। इसके साथ ही इस दौरान प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सक्रियता कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी।

संघ की विचाराधारा अपना रहे सीएम चंद्रबाबू नायडू: शर्मिला

आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने दलित बस्तियों में मंदिर बनाने के लिए तिरुपति मंदिर के बजट का उपयोग करने पर सीएम चंद्रबाबू नायडू पर हमला बोला। शर्मिला ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने आरएसएस की विचारधारा को अपना लिया है। मंदिर निर्माण के बजाय तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) अपने धन का उपयोग दलित बस्तियों में बुनियादी ढांचे और विकास के लिए करे। विजयवाड़ा के अजित सिंह नगर में शर्मिला ने सीएम चंद्रबाबू नायडू से पूछा कि आप दलित बस्तियों के विकास के लिए टीटीडी के अतिरिक्त फंड का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? यदि नायडू वास्तव में दलितों के उत्थान में रुचि रखते हैं, तो वह उनके विकास पर ध्यान क्यों नहीं दे सकते? कल्याण छात्रावास में 200 छात्राएं एक ही शौचालय का उपयोग करने के लिए मजबूर हैं।

उन्होंने सवाल उठाया कि नायडू टीटीडी फंड से दलितों की आवश्यकताओं की पूर्ति करके छात्रावासों में सुविधाएं क्यों नहीं प्रदान कर सकते और दलित बस्तियों में स्वच्छता पर ध्यान क्यों नहीं दे सकते? अगर दलित बस्तियों में मंदिर बनाए गए, तो उनमें पुजारी कौन होगा? आप ब्राह्मणों को पुजारी नियुक्त करेंगे या दलितों को?

पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध गिरोह का किया पर्दाफाश,

अहमदाबाद

गुजरात पुलिस ने एक अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध गिरोह का पदार्फाश किया है, जिसने भारत के नागरिकों को 804 करोड़ रुपये का चूना लगाया। राज्य के गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी ने शनिवार को यह जानकारी दी। गिरोह के 10 आरोपियों को सूरत से गिरफ्तार किया गया। गिरोह ने दुबई, वियतनाम और कंबोडिया से ऑपरेशन किया और पूरे भारत में नागरिकों को निशाना बनाया।

गिरोह आम नागरिकों के बैंक खाते और सिम कार्ड 1.5-2 प्रतिशत कमीशन के लालच में हासिल करता था और उनका दुरुपयोग कर साइबर ठगी करता था। गिरोह ने पूरे देश में 1,549 अपराध किए और 804 करोड़ रुपये की ठगी की। गुजरात में 141 डिजिटल अपराधों के जरिए गिरोह ने 17.75 करोड़ कमाए। सूरत से गिरफ्तार आरोपियों के पास से 65 मोबाइल फोन, 447 डेबिट कार्ड, 529 बैंक खाता किट, 686 सिम कार्ड और 16 पॉइंट ऑफ सेल मशीनें जब्त की गईं।

द. अमेरिकी देशों के दौरे पर निकले राहुल, नेताओं और छात्रों से करेंगे मुलाकात

नई दिल्ली

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शनिवार को चार दक्षिण अमेरिकी देशों की यात्रा पर रवाना हो गए। इस दौरान वे राजनीतिक लोगों, छात्रों और कारोबारियों से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस की मीडिया और प्रचार विभाग के प्रभारी पवन खेड़ा ने यह जानकारी दी। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि राहुल गांधी कितने दिन देश से बाहर रहेंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दक्षिण अमेरिकी देशों की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। वे चार देशों में राजनीतिक नेताओं, विश्वविद्यालय के छात्रों और कारोबारी जगत से जुड़े लोगों से संवाद करेंगे। कांग्रेस के अनुसार राहुल गांधी ब्राजील और कोलंबिया जाएंगे, जहां वे विश्वविद्यालय के छात्रों से बातचीत करेंगे। बताया जा रहा है कि राहुल की यह यात्रा 10 दिन की है। इस दौरान वह पेरू, चिली, ब्राजील और कोलंबिया जाएंगे।

कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ब्राजील, कोलंबिया और अन्य जगहों का दौरा करेंगे, जहां उनके विश्वविद्यालय के छात्रों से बातचीत करने की उम्मीद है। पार्टी ने कहा कि वह कई देशों के राष्ट्रपतियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकें करेंगे और लोकतांत्रिक एवं रणनीतिक संबंधों को मजबूत करेंगे।

पार्टी ने यह भी कहा कि अमेरिकी शुल्क के मद्देनजर भारतीय व्यापार और साझेदारी में विविधता लाने के अपने प्रयासों के तहत, राहुल गांधी व्यापार जगत के प्रमुख लोगों के साथ मिलकर अवसरों की तलाश करेंगे। वह ब्राजील, कोलंबिया और अन्य जगहों के विश्वविद्यालयों के छात्रों से बातचीत करेंगे और वैश्विक नेताओं की अगली पीढ़ी के साथ संवाद स्थापित करेंगे। कांग्रेस ने कहा कि यह महत्वपूर्ण यात्रा ऐतिहासिक महत्व रखती है। कांग्रेस ने कहा कि भारत और दक्षिण अमेरिका ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ह्यग्लोबल साउथह्न में एकजुटता और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से लंबे समय से अपने संबंध साझा किए हैं। मुख्य विपक्षी दल के अनुसार, राहुल गांधी का यह अभियान इस परंपरा को जारी रखते हुए व्यापार, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच आपसी आदान-प्रदान में सहयोग के नए रास्ते खोल रहा है।पार्टी ने यह भी कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को आकार देने और भारत की वैश्विक उपस्थिति को आगे बढ़ाने में भारत के लोकतांत्रिक विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

मणिपुर: असम राइफल्स के काफिले पर हमले करने वाले दो उग्रवादी गिरफ्तार

इंफाल

सुरक्षा बलों ने मणिपुर में 19 सितंबर को असम राइफल्स के काफिले पर हुए हमले में कथित संलिप्तता के आरोप में एक प्रतिबंधित संगठन के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस हमले में असम राइफल्स के दो जवान बलिदान हो गए थे। गिरफ्तार किए गए एक उग्रवादी को गुवाहाटी से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक बयान में कहा गया है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के दो कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। ये 19 सितंबर को बिष्णुपुर जिले के नाम्बोल सबल लेईकाई में 33 असम राइफल्स पर हुए हमले में मुख्य रूप से शामिल थे। गिरफ्तार किए गए आतंकियों में से एक को असम की राजधानी गुवाहाटी से पकड़ा गया, जबकि दूसरे की गिरफ्तारी का स्थान पुलिस ने उजागर नहीं किया। 19 सितंबर को अर्धसैनिक बलों के एक वाहन पर हथियारबंद लोगों के एक समूह द्वारा घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में असम राइफल्स के दो जवान बलिदान हो गए और पांच अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान थोंग्राम सदानंद सिंह उर्फ नगाचिक उर्फ पुरकपा (18) और स्वयंभू लेफ्टिनेंट कॉर्पल चोंगथम महेश उर्फ मोमो (51) के रूप में हुई है।

दिल्ली की 1000 सरकारी इमारतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की शुरूआत कर मुबारकपुर डबास में 66 केवी ग्रिड सब-स्टेशन की आधारशिला रखी

सीएम ने पीतमपुरा में विकास कार्यों का किया शुभारंभ

सोलर रूफटॉप हर वर्ष 28,000 से अधिक यूनिट स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करेगा

नई दिल्ली

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को पीतमपुरा के विभिन्न ब्लॉकों में नई सीवर लाइनें, पानी की लाइनें और आधारभूत संरचना से संबंधित विकास कार्यों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार एक ओर जहां सीवर और पानी जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर रही है, वहीं दूसरी ओर एलिवेटेड रोड, छठ घाट और घर-घर तक गैस पाइपलाइन जैसी बड़ी परियोजनाएं दिल्ली के भविष्य को नई दिशा दे रही हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार दिन-रात लगातार काम कर रही है। सड़कों और आधारभूत संरचनाओं को नई मजबूती मिली है, स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक सशक्त हुई हैं, हरित ऊर्जा और स्वच्छता को नई दिशा मिली है। हर क्षेत्र में तेजी से हो रहा यह बदलाव दिल्लीवासियों के जीवन को और आसान तथा बेहतर बना रहा है। उन्होंने सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि माता रानी की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो।

दिल्ली में 16वीं चैपियंस रन का आयोजन, 'हम फिट तो इंडिया फिट' का दिया संदेश

विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर शनिवार को दिल्ली के गांधी दर्शन स्थल पर 16वीं चैपियंस रन का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने किया। साथ ही रन पूरी होने के बाद विजेताओं को सम्मानित करने के लिए पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन भी किया गया। दिल्ली में हेल्थ फिटनेस ट्रस्ट ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आयोजित 16वीं चैपियन रन में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। 'हम फिट तो इंडिया फिट' के संदेश के साथ चैपियन रन के माध्यम से देशवासियों में फिटनेस के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया गया। इस आयोजन में दिल्ली पर्यटन विभाग के अलावा गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी साझेदार रहे। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने ग्रेटर कैलाश में ऑटोमेटेड मल्टीलेवल शटल पार्किंग का किया उद्घाटन

नई दिल्ली

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को ग्रेटर कैलाश एम-ब्लॉक मार्केट में दिल्ली नगर निगम द्वारा निर्मित अत्याधुनिक ऑटोमेटेड मल्टीलेवल शटल पार्किंग का उद्घाटन किया। शटल पार्किंग में एक रोबोटिक शटल वाहन को अंतिम स्थान पर ले जाकर जाता है। इस अवसर पर महापौर राजा इकबाल सिंह, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद, सांसद बांसुरी स्वराज, विधायक शिखा राय उपस्थित रहीं। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि यह पार्किंग सिस्टम ट्रैफिक जाम को कम करेगा और नागरिकों को सुरक्षित-व्यवस्थित पार्किंग की सुविधा प्रदान करेगा। इससे राजधानी की यातायात व्यवस्था अधिक सुचारू और सुविधाजनक बनेगी।

मुख्यमंत्री ने आश्वस्त करते हुए कहा कि जनता की सुविधा और विकास कार्यों के लिए कभी फंड की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शटल और पजल पार्किंग जैसी आधुनिक परियोजनाओं से दिल्ली की पार्किंग समस्याओं का स्थायी समाधान होगा।

बाबा साहेब के आदर्शों पर चल रही दिल्ली सरकार : रविंद्र इंद्राज

नई दिल्ली

"भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि सत्ता से अधिक महत्वपूर्ण सत्य और आत्म-सम्मान है। दिल्ली सरकार उनके आदर्शों पर चलकर न्याय, समानता और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में कार्य कर रही है।" यह बात दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने कहीं। उन्होंने शनिवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय आत्म-सम्मान दिवस कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले के साथ सहभागिता की। इस अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह, कलिंदी कॉलेज की प्राचार्य प्रो. मीना चरंडा, समाजशास्त्र संकाय के डीन प्रो. संजॉय रॉय उपस्थित रहे।

मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने कहा कि 27 सितंबर 1951 को डॉ. आंबेडकर ने महिलाओं और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा हेतु नेहरू सरकार में अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, इसलिए यह दिन राष्ट्रीय आत्म-सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि यह केवल बाबा साहेब का व्यक्तिगत निर्णय नहीं, बल्कि पूरे समाज को न्याय और समानता के मार्ग पर ले जाने वाला ऐतिहासिक कदम था। उन्होंने महिलाओं को संपत्ति, विवाह और उत्तराधिकार में समान अधिकार दिलाने का प्रयास किया लेकिन उस समय की सरकार ने इसकी अनदेखी की। बाबा साहेब का पूरा जीवन गरीब, दलित, वंचितों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समर्पित रहा।

कोर्ट ने सांसद चंदोलिया के खिलाफ मामले में 2 गवाहों को किया तलब

नई दिल्ली

दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया के खिलाफ एक सरकारी कर्मचारी पर हमला करने के मामले में अभियोजन पक्ष के दो गवाहों को समन जारी किया है। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को करने का आदेश दिया। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 5 मई को योगेंद्र चंदोलिया के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। इस मामले में चंदोलिया के खिलाफ साल 2020 में दिल्ली के प्रसाद नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में तीस हजारी कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए 17 अक्टूबर 2023 को चंदोलिया को समन जारी किया था। योगेंद्र चंदोलिया ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है। साल 2020 में दिल्ली के प्रसाद नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में तीस हजारी कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए 17 अक्टूबर, 2023 को चंदोलिया को समन जारी किया था।

साइबर पुलिस ने एयरफोर्स अधिकारी बनकर ठगी करने वाले ठग को दबोचा

नई दिल्ली

दक्षिणी जिले की साइबर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एयरफोर्स अधिकारी बनकर ठगी करने वाले एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान अलवर राजस्थान निवासी तसलीम खान (20) के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से अपराध में इस्तेमाल किए गए दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं। दक्षिणी जिले के पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने शनिवार को बताया कि यह मामला उस समय सामने आया जब छतरपुर निवासी एक महिला ने साइबर थाना दक्षिण में एक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार, आरोपित ने खुद को एयरफोर्स का अधिकारी बताकर महिला को फर्जी इनवॉइस और पत्र दिखाए और टोकन फीस, सिक्योरिटी चेक व गेट पास औपचारिकताओं के नाम पर 2.52 लाख रुपये ठग लिए। शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करके जांच शुरू की। एसएचओ साइबर थाना दक्षिण इंस्पेक्टर हंसराज स्वामी के नेतृत्व में एक टीम ने तकनीकी निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाई। जिसमें आरोपित का लोकेशन अलवर (राजस्थान) में मिला। इसके बाद टीम ने अलवर के गांव मुकंदवास, रामगढ़ में छापेमारी कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपित क्विकर प्लेटफॉर्म पर एयरफोर्स अधिकारी बनकर लोगों को झांसे में लेता था।

अब तक देशभर में आरोपित द्वारा ठगे गए 7 पीड़ितों की पहचान की है

बरामद मोबाइल से मिले व्हाट्सएप चैट के आधार पर अब तक देशभर में आरोपित द्वारा ठगे गए 7 पीड़ितों की पहचान की है। पुलिस अब आरोपित से पूछताछ कर उसके साथियों और अन्य पीड़ितों की तलाश में जुटी है।

3580 किग्रा अवैध पटाखे समेत तीन गिरफ्तार

नई दिल्ली

पश्चिमी जिले की स्पेशल स्टाफ ने अवैध पटाखों के साथ एक ही परिवार के तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके घर से पुलिस को 3580.4 किलोग्राम पटाखे बरामद हुए हैं। आरोपितों ने राजौरी गार्डन के आवासीय इलाके में स्थित अपने घर के अंदर ही पटाखे का गोदाम बना रखा था और गुरुवार को इनको पटाखों की पैकेजिंग के दौरान रंगे हाथ पकड़ा गया। ये लोग मेरठ, गुरुग्राम और गाजियाबाद से पटाखे लाकर दिल्ली में ज्यादा मुनाफे पर बेचते थे। पुलिस के मुताबिक, गुप्त सूचना के आधार पर गुरुवार सुबह टीम ने विशाल एन्क्लेव, राजौरी गार्डन स्थित घर में छापेमारी के बाद आरोपितों को दबोच लिया। इनकी पहचान पति सुशील कक्कड़, पत्नी उपासना कक्कड़ और बेटे शिवम कक्कड़ के रूप में हुई है।

ये लोग इलाके में एक नमकीन व अन्य खाद्य पदार्थों की दुकान चलाते हैं।

नदी जागरूकता को लेकर वृत्तचित्र फिल्में दिखाई गईं

नई दिल्ली

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) में 25 से 27 सितंबर तक आयोजित तीन दिवसीय छठे नदी उत्सव' के अंतिम दिन शनिवार को 'रिवर ऑफ रेजोनेंसः शरावती शिवमोग' और 'कावेरीः जीवन की नदी' सहित कई वृत्तचित्र फिल्में दिखाई गईं। रिवर ऑफ रेजोनेंसः शरावती शिवमोग फिल्म के निमार्ता-निर्देशक याजी हैं। कन्नड़ में निर्मित यह फिल्म शरावती नदी पर केंद्रित है। फिल्म को प्रकृति और बदलते पर्यावरण पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए फिल्माया गया है। इसमें दिखाया गया है कि नदी और एक लड़के के बीच ह्यमाँ-बेटेह्न जैसा रिश्ता होता है, जिसका आशय है नदी केवल जल नहीं, बल्कि जीवन देने वाली माँ है। बच्चे की मासूमियत से दर्शक यह समझते हैं कि हम प्रकृति के साथ कैसे जुड़ते हैं और कैसे उसका नुकसान हमें भीतर से तोड़ता है। इस फिल्म के एक सहयोगी गणेश ने बताया कि रिवर ऑफ रेजोनेंस फिल्म शरावती नदी और उसके इर्द-गिर्द रहने वाले लोगों के बीच के रिश्ते और भावनात्मक लगाव को व्यक्त करती है। कर्नाटक के करावली क्षेत्र (पश्चिमी तट) में बहने वाली शरावती नदी पर मानवीय दखल और "अप्राकृतिक बदलाव" हो रहे हैं। इन बदलावों के पीछे मानवीय हस्तक्षेप है। उन्होंने बताया कि नदी अपने तट पर बसे लोगों और सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लोगों को पीने का पानी, खेती, मत्स्य पालन में मदद करती है। इसके अलावा त्योहार, लोककथाएं भी इस नदी पर निर्भर हैं, लेकिन बदलती जलवायु, परियोजनाएं और मानव हस्तक्षेप इस संतुलन को तोड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस फिल्म को गर्मी और मानसून दोनों मौसम में फिल्माया गया है ताकि दर्शकों को दिखाया जा सके कि दोनों ऋतुओं में नदी की स्थिति कैसी होती है। इसी तरह एक अन्य अंग्रेजी फिल्म 'कावेरीः जीवन की नदी' की भी स्क्रीनिंग की गई। इस फिल्म में दिखाया गया है कि नदी एमएम हिल्स और कावेरी वन्यजीव अभयारण्यों से होकर बहती है। जिससे यह क्षेत्र सुंदर और प्राकृतिक वातावरण से हरा भरा दिखाई पड़ता है। फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि नदी के किनारे छोटे और बड़े जीव कैसे साथ रहते हैं। यह फिल्म प्रकृति के कई छिपे हुए रहस्यों को भी दिखाती है। नदी जीवन के संतुलन का एक अहम हिस्सा है। इस दौरान 'गोताखोरः डिसपियरिंग डाइविंग कम्युनिटी', 'रिवर मैन ऑफ इंडिया', 'अर्थ गंगा', 'मोलाईझ मैन बिहाइंड द फॉरेस्ट' और 'लद्दाख- लाइफ अलॉन्ग द इंडस' जैसी समाज को नदियों को लेकर जागरूक करने वाली अन्य फिल्में भी दिखाई गईं।

पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपित गगनप्रीत कौर को दी जमानत

नई दिल्ली। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने धौला कुआं इलाके में हुए बीएमडब्ल्यू कांड मामले की आरोपित गगनप्रीत कौर को जमानत दे दी है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अंकित गर्ग ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने गगनप्रीत कौर को एक लाख के निजी बेल बांड पर और इतनी ही रकम के दो जमानतियों के आधार पर जमानत देने का आदेश दिया।

अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का विश्व कायस्थ सम्मेलन 23 अक्टूबर से

नई दिल्ली

अखिल भारतीय कायस्थ महासभा और चित्रांश चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (सीसीसीआई) ने विश्व कायस्थ सम्मेलन, 2025 के आयोजन करने का ऐलान किया है। राजधानी नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 23-24 अक्टूबर को दो दिवसीय इस सम्मेलन का आयोजन होगा। महासभा के राष्ट्रीय चेयरमैन डॉ. अभिषेक वर्मा ने शनिवार को यहां आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में इसकी जानकारी दी। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा (पंजीकृत 2150, नई दिल्ली) के राष्ट्रीय चेयरमैन डॉ. अभिषेक वर्मा ने संवाददाताओ को सम्मेलन की जानकारी देते हुए बताया कि यह सम्मेलन यम द्वितीया (भाई दूज) के शुभ अवसर पर 23-24 अक्टूबर को आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि यम द्वितीया परंपरागत रूप से भगवान चित्रगुप्त की पूजा के साथ मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन कायस्थ समुदाय के लिए एकजुट होने और अपनी ताकत प्रदर्शित करने का एक ऐतिहासिक अवसर होगा।

मुस्लिम महासम्मलेनः वक्फ संशोधन कानून पर की गयी सराहना

नई दिल्ली

मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने आज यहां के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में अखिल भारतीय मुस्लिम महासम्मलेन का आयोजन किया। इसमें देश के विभिन्न हिस्सों से उलमा, सूफी, बुद्धिजीवी, शिक्षाविद एक मंच पर एकत्रित हुए। सम्मेलन में देश के अलग-अलग राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से लगभग 12 हजार लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ कुरान-ए-पाक की तिलावत से किया गया। इस महासम्मलेन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष प्रो. शाहिद अख्तर, वक्फ संशोधिन विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के चेयरमैन सांसद जगदंबिका पाल, अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख मौलाना उमैर इलियासी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्य नारायण जटिया के अलावा क्षेत्रीय, प्रांतीय एवं राष्ट्रीय संयोजकों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर इंद्रेश कुमार ने कहा कि इस महासम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य मुस्लिम नेतृत्व की नई रणनीति बनाना, राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर चर्चा करना, सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना और एक ठोस रूपरेखा तैयार करना है, जिससे समुदाय की आकांक्षाओं को भारत की विकास यात्रा से जोड़ा जा सके।

आईपीयू ने राष्ट्रीय सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित किया आउटरीच कार्यक्रम

नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे राष्ट्रीय सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (आईपीयू) के छात्रों ने शनिवार को जेजे कॉलोनी गांव में एक विशेष आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय समुदाय को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना और जमीनी स्तर पर सहायता उपलब्ध कराना था। कार्यक्रम कुलपति प्रो. महेश वर्मा के मार्गदर्शन में हुआ, जिसमें रजिस्ट्रार डॉ. कमल पाठक, निदेशक प्रो. वंदना सिंह और सेंटर आउटरीच एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज के एसोसिएट प्रोजेक्ट निदेशक डॉ. जुबैर अहमद खान शामिल हुए।

छात्रों ने ग्रामीणों को आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कई प्रमुख योजनाओं के लाभ और प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया। इसके साथ ही उन्होंने आवश्यक विवरण इकट्ठा करने और फॉर्म भरने में भी मदद की, ताकि लाभार्थियों को योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। इसके साथ ही, जेजे कॉलोनी में स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया जहां स्थानीय निवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और परामर्श सेवाएं प्रदान की गईं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि यह पहल समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने और छात्रों में सेवा की भावना को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जीजीएसआईपीयू का उद्देश्य है कि छात्र न केवल अकादमिक रूप से उत्कृष्ट हों, बल्कि राष्ट्र निर्माण और सामाजिक कल्याण में भी सक्रिय योगदान दें।

आरोपित ने पत्नी और बेटे को मारी गोली

नई दिल्ली

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दयालपुर स्थित मूंगा नगर इलाके में शनिवार दोपहर पारिवारिक विवाद में एक शख्स ने पत्नी को गोली मार दी। वारदात के बाद उसका बेटा मां को बचाने आया तो आरोपित ने उस पर भी गोली चला दी। बाद में आरोपित मौके से फरार हो गया। गोली चलने की आवाज सुनते ही मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई। आनन-फानन में मां रिजवाना परवीन (40) और इनके बेटे अरबाज (17) को शास्त्री पार्क स्थित जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों की हालत देखते हुए इनको जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया। अस्पताल में रिजवाना की हालत गंभीर बनी हुई है। इनके सीने में गोली लगी हुई है। गोली चलने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। बाद में क्राइम टीम व एफएसएल को मौके पर बुला लिया गया। टीम को घर से चार खोखे बरामद हुए हैं। जिला पुलिस उपायुक्त आशीष मिश्रा ने बताया कि हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपित अब्दुल करीम की तलाश शुरू कर दी गई। उसकी तलाश में तीन टीमों को लगाया गया है।

संपादकीय

अस्पतालों में पुस्तकालय

तमिलनाडु के तिरुचि के महात्मा गांधी मेमोरियल सरकारी अस्पताल में एक उपेक्षित कोने में शुरू हुआ पुस्तकालय मरीजों, तीमारदारों और कर्मचारियों के लिए सुकून, ज्ञान और समय बिताने का माध्यम बन गया है। यहां कुछ पुस्तकें, पत्रिकाएं और अंग्रेजी-तमिल अखबार उपलब्ध हैं। कोविड काल में यह सिद्ध हो चुका है कि मनोरंजक किताबें मरीजों के उपचार में बेहद सहायक होती हैं।

कोविड की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली से सटे गाजियाबाद में कोरोना के लक्षण वाले मरीजों को एकांतवास में रखा जाता था। लेकिन आए दिन एकांतवास केंद्रों से मरीजों के झगड़े या तनाव की खबरें आ रही थीं। तब जिला प्रशासन ने नेशनल बुक ट्रस्ट के सहयोग से लगभग 200 बच्चों की पुस्तकें वहां वितरित कर दीं। रंग-बिरंगी पुस्तकों ने मरीजों के दिल में जगह बना ली और वे खुश नजर आने लगे। उनका समय पंख लगाकर उड़ गया। डॉक्टरों ने भी माना कि पुस्तकों ने क्वारंटीन किए गए लोगों का तनाव कम किया, उन्हें गहरी नींद आई और सकारात्मकता का संचार हुआ। इससे उनकी स्वास्थ्य लाभ की गति भी बढ़ी।

दिल्ली में भी छतरपुर स्थित राधास्वामी सत्संग में बनाए गए विश्व के सबसे बड़े क्वारंटीन सेंटर में हजारों पुस्तकों के साथ लाइब्रेरी शुरू करने की पहल की गई। यहां नेशनल बुक ट्रस्ट ने एक हजार किताबों के साथ उनकी पत्रिका ह्यपाठक मंचह्ल बुलेटिन और ह्यपुस्तक संस्कृतिह्ल के सौ-सौ अंक भी रखे। वहां भर्ती मरीज जल्दी स्वस्थ और प्रसन्न दिखे।

देश के अस्पतालों में मरीजों के साथ आने वाले तीमारदारों की उपस्थिति भीड़ और अव्यवस्था का बड़ा कारण है, क्योंकि वे अक्सर बिना काम के प्रतीक्षा क्षेत्र में समय बिताते हैं और मानसिक थकान का शिकार हो जाते हैं, जिससे अस्पताल प्रणाली पर भी दबाव बढ़ता है। तिरुची के अस्पताल के पुस्तकालय ने ऐसे तीमारदारों को सकारात्मक और व्यस्त रखने का समाधान खोजा है। दुनिया के विकसित देशों के अस्पतालों में पुस्तकालय की व्यवस्था का इतिहास सौ साल से भी पुराना है। अमेरिका में 1917 में सेना के अस्पतालों में लगभग 170 पुस्तकालय स्थापित किए गए थे। ब्रिटेन में सन? 1919 में वार लाइब्रेरी की शुरूआत हुई। इसके बाद आज अधिकांश यूरोपीय देशों के अस्पतालों में मरीजों को व्यस्त रखने और ठीक होने का भरोसा देने के लिए ऐसी पुस्तकों की व्यवस्था है। ऑस्ट्रेलिया के सार्वजनिक अस्पतालों में तो आम लोग भी पुस्तकें पढ़ने के लिए ले सकते हैं। इंग्लैंड के मैनचेस्टर के क्रिस्टी कैंसर अस्पताल का पुस्तकालय तो पुस्तकों का वर्गीकरण रंगों के अनुसार करता है। जापान के अस्पतालों में बच्चों की किताबें बहुतायत में मिलती हैं और उन्हें अक्सर वयस्क ही पढ़ते हैं।

भारत में तकरीबन अड़तीस हजार अस्पताल हैं, जिनमें कोई आठ लाख से अधिक मरीज हर दिन भर्ती होते हैं। इनके साथ तिमारदार भी होते हैं। अनुमान है कि कोई बीस लाख लोग चौबीसों घंटे अस्पताल परिसर में होते हैं। इनमें बीस फीसदी ही बेहद गंभीर होते हैं, शेष लोग बुद्धि से चैतन्य और ऐसी अवस्था में होते हैं जहां उन्हें बिस्तर पर लेटने या बाहर अपने मरीज का इंतजार करना एक उकताहट भरा काम होता है।

आमतौर पर बड़े अस्पतालों में मरीजों और तीमारदारों के लिए लगाए गए टीवी, अक्सर तनाव बढ़ाने वाले कार्यक्रम दिखाते हैं, जबकि मोबाइल फोन अफवाहों और झूठी सूचनाओं का जरिया बन चुके हैं। इससे मरीजों का मानसिक संतुलन और तीमारदारों की शांति दोनों प्रभावित होती है। सर्वविदित है कि पुस्तकें एकांत में सबसे अच्छा साथ निभाती हैं। ये काले छपे हुए शब्द, दर्द और उदासी के दौर में दवा का काम करते हैं। हर किसी की जिंदगी में कुछ अच्छी किताबों का होना जरूरी है। किताबें सिर्फ मनोरंजन या इम्तिहान उत्तीर्ण करने के लिए नहीं होतीं, जिंदगी के रास्ते बनाने के लिए होती हैं। किताबों में हर मुश्किल सवाल, परिस्थिति का हल भले ही न छुपा हो लेकिन दुविधा काल में किताबों में पढ़ने से, समझने से उसकी सोच का सकारात्मक विस्तार होता है। लोगों को एक सात्विक मानसिक खुराक दे सकती हैं, जो उनके जल्दी रोगमुक्त होने में सहायक हो सकता है।

बढ़े दमखम के साथ महिला स्वावलंबन

महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के 2017 में जब सौ वर्ष पूरे हुए तो अहिंसा के इस ऐतिहासिक प्रयोग को लेकर कई सारे किताबें आईं। लेखकों और शोधार्थियों ने तब के गांधी के अनुभवों और उस दौरान के घटनाक्रम के आधार पर कई नए तथ्यों को उजागर किया। इसमें सबसे अहम है गांधी और कस्तूरबा का यह साझा अनुभव कि बिहार की महिलाएं जागरूक हैं और उनमें अपने बूते खड़ा होने का माद्दा है। अगर उनके आगे कोई बाधा है तो वह समाज और व्यवस्था का लैंगिक वह पूर्वाग्रह, जिसकी जड़ें खासी गहरी हैं। आज की तारीख में इस बात को देखना-समझना तब बेहद अहम और दिलचस्प हो जाता है जब हम देखते हैं कि बिहार ने बीते दो दशक में देश को महिला सशक्तीकरण का एक टिकाऊ मॉडल दिया है। यह एक ऐसा मॉडल है जो सामुदायिकता के बूते बड़े सामाजिक बदलाव को संभव बना रहा है।

बिहार की चर्चा इन दिनों जरूर होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही है, पर इससे जुड़ी तमाम सियासी गहमागहमी के बीच यह बात खासतौर पर समझने की है कि आज राजनीति से लेकर समाज और आर्थिकी तक हर क्षेत्र में जेंडर इक्वलिटी या लैंगिक समानता की बात लाजिमी तौर पर होती है। वैसे भी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र विधानसभा के चुनावी नतीजे ने यह दिखा दिया है कि अब चुनावों का संतुलन महिलाएं साध रही है। यह देश में सामाजिक के साथ राजनीतिक बदलाव का एक बड़ा संकेत है।

बिहार में सामाजिक और आर्थिक बदलाव की नई लहर उस समय शुरू हुई जब नीतीश कुमार ने राज्य की बागडोर संभाली। वे अपनी इस समझ और विवेक में बहुत साफ रहे कि अगर समाज को सशक्त बनाना है, तो महिलाओं को सिर्फ लाभार्थी नहीं, बल्कि विकास की भागीदार बनाना होगा। इसी सोच के साथ नीतीश सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अनेक योजनाएं चलाईं, जिनका उद्देश्य है महिला स्वरोजगार। चुनाव से पूर्व होने वाली अव्यावहारिक और हवाई घोषणाओं से अलग बिहार सरकार ने कैबिनेट स्तर पर इस दौरान कई अहम फैसले लिए हैं। इस क्रम में जो बड़ा फैसला राज्य सरकार ने किया है, वह है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। गौरतलब है कि इस निर्णय से पहले 70 हजार महिला समूहों के साथ सरकार ने महिला संवाद किया। साफ है कि सरकार ने इस योजना को प्रदेश की महिलाओं की स्थिति और जरूरत को समझते हुए न सिर्फ फ्रेम किया, बल्कि इसके शीघ्र क्रियान्वयन को लेकर भी वह लगातार गंभीर रही।

आज जब प्रदेश की 75 लाख महिलाओं के खाते में दस-दस हजार रुपए की राशि पहुंच रही है तो यह महिला स्वावलंबन को लेकर सरकार की दृष्टि और संकल्प शक्ति दोनों जाहिर करती है।

महिलाओं को यह राशि योजना के तहत मिलने वाली दस हजार रुपए की पहली किस्त के तौर पर मिली है। छह महीने बाद मूल्यांकन के बाद इन महिलाओं को दो लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। बात महिला सशक्तीकरण की हो रही है तो यह जान लेना जरूरी है बिहार में नीतीश सरकार की सबसे सफल योजनाओं में जीविका विशेष स्थान रखती है। वर्ष 2006 में शुरू हुई इस योजना ने ग्रामीण महिलाओं को न केवल स्वरोजगार का अवसर दिया, बल्कि उन्हें नेतृत्व का अभ्यास भी कराया।

सोनम वांगचुक जैसे लोग देश की अखंडता के लिए खतरा

काश्मीर में अशांति पैदा कर रहें

प्रोफेसर (डॉ.)तेजसिंह किराड़
(वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक, नागपुर)

समाज सेवा की आड़ में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वाले सोनम वांगचुक जैसे चेहरों पर से अब नकाब उठाने का समय आ गया है। लेह में आगजनी की घटना और भाजपा कार्यालय में तोड़फोड़,निजी और राष्ट्रीय सम्पत्तियों का भारी नुकसान स्पष्ट करता है कि काश्मीर की शांति ना तो अलगाववादियों को रास आ रही है और ना ही बाप- बेटे उमर और फारुख अब्दुल्ला को भारत की अखंडता के मायने समझ में आ रहें हैं। लेह में घटित घटना अकेले सोनम वांगचुक के बस की बात नहीं है, जरूर इसके पीछे ऐसे तथाकथित चेहरे हैं जो भारत के अंदर सोची समझी साजिश के तहत एक गृह युद्ध कि चिनगारी को जन्म दे रहे हैं।हाल ही में नेपाल में जो सत्ता परिवर्तन के साथ मौत औल आगजनी का खौफनाक तांडव मचाया गया था, वही परिभाषा भारत में लिखे जाने कि कयावद सोनम वांगचुक जैसे देश द्रोही समाज सेवा की आड़ में देश की संप्रभुता को भी सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला का बयान, कि केंद्र सरकार जल्दी समाधान ढूंढे अन्यथा और भी गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं, फारूख अब्दुल्ला कि यह टिप्पणी भी बेहद गंभीर और देश के लिए खतरा उत्पन्न करने वाली प्रतीक होती है। सच तो यह हैं कि उमर अब्दुल्ला, फारुख अब्दुल्ला मेहबूबा मुफ्ती मोहम्मद जैसे नेताओं ने काश्मीर की सरकार चलाई परन्तु काश्मीर को हमेशा से भारत से अलग समझने की बहुत बड़ी भूल भी करते रहें हैं। जग जाहिर है कि अब्दुल्ला खानदान और

मेहबूबा ने अखंड भारत को कभी महत्व ही नहीं दिया। इन्होंने काश्मीर में सरकार चलाते हुए ना तो काश्मीरियों के पुनर्वास, उनके विकास,और ना ही उनकी जीवन संरक्षण, जीवनशैली से जुड़ी प्राथमिकताओं को कभी महत्व दिया। देश के अन्य राज्यों की जनता को गुमराह कर-के अपनी राजनैतिक रोटियां सेंकने वाले अब्दुल्ला और मुफ्ती खानदान आज भी काश्मीर में अलगाववाद की भाषा बोलकर राष्ट्रीय अखंडता के विरोध में भड़काऊ भाषण देने से बाज नहीं आ रहे है। अब्दुला को एक और सोनम वांगचुक जैसा चेहरा भी अलगाववादी के रूप में मिल चुका है। नेपाल कि घटना को काश्मीर में लागू करके ना जाने क्या सिद्ध करने का प्लान था यह तो जो पकड़े गए हैं वही सच्चाई को बयां करेंगे।

काश्मीर में अमन चेन शांति के लिए जो संघर्ष मोदी की केन्द्र सरकार ने किया है वह कल्पनातीत है। मोदी मतलब एकमेव भाजपा समझने वाले सभी विपक्षी दल पिछले ग्यारह वर्षों से विपक्ष में बैठकर मोदी को हराने का कोई ठोस प्लान आज तक नहीं बना पाए हैं। गाली गलोच, अपमान जनक टिप्पणियां, भड़काऊ भाषण, विकास के अच्छे परिणामों पर भी टीका करना तमाम विपक्षियों ने एक हथियार बना लिया है। विपक्षियों के लिए यह सबसे बड़ी हार है कि वे चालीस दल एकजुट होकर भी मोदी को हरा नहीं पा रहें हैं।और मोदी है कि जनता के विश्वास, विकास और सबका साथ लेकर रोज हर दिन एक नया इतिहास रचते जा रहें हैं। विपक्ष एकजुट का दिखावा करके भी खंड खंड हो चुका है। आजादी के बाद की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस कि हालत इतनी पतली हो चुकी है कि उसे देश में होने वाले हर स्तरीय चुनावों लोकसभा,विधानसभा, महानगर पालिका, नगर पंचायत,नगर परिषद और पंचायत चुनाव में भी सीट शेयरिंग करना पड़ रहीं और बुरी तरह से हाल भी रही है। कांग्रेस की यही हताशा और निराशा देश में हर आंदोलन में आगे खड़ी होकर भड़काऊ भाषण देने,जहर उगलने,देश द्रोहियों को संरक्षण देने,उनका पक्ष लेने, विदेशों में भारत की साख को धूमिल करने जैसे कार्यों को ही चुनावी मुद्दा बना कर आम जनता को गुमराह कर रही है। कांग्रेस के ही नक्शे कदमों पर चलने वाले अन्य दलों में शिवसेना युबीटी,सपा, बसपा, ममता बनर्जी की टीएमसी,अब्दुल्ला की नेशनल कांग्रेस जैसे दलों को देश की अखंडता, संप्रभुता और आर्थिक विकास से कोई सरोकार नहीं रह गया है। बस! सत्ता कैसे

मिलेगी यही सोच सोच कर इन दलों के नेताओं की मानसिक स्थिति भी लगभग बिगड़ चुकी है।

सोनम वांगचुक का एनजीओ संदेह में!

वांगचुक कि यह भड़ास किसी एक दिन का परिणाम नहीं है। अपने एनजीओ हिमालयन इंस्टिट्यूट ऑफ अल्टरनेटिवस लद्दाख में जांच पड़ताल के लिए सीबीआई टीम ने दबिश भी डाली थी। क्योंकि वांगचुक संस्था के समाजसेवी कार्य के नाम पर विदेशी फंड असंवैधानिक रूप से बड़ी मात्रा में लेकर देश की अखंडता के लिए खतरा पैदा करने का अभियान विगत कई वर्षों से चला रहें हैं। कल हुई घटनाओं और भाजपा कार्यालय को जलाने की घटना से उनके सारे छिपे देश विद्रोही कार्य सामने आ गये है। वांगचुक चाहते हैं कि लद्दाख को केन्द्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया जाएं। ताकि वे काश्मीर के अलगाववादियों के साथ मिलकर फिर से वही माहौल को जन्म दे सके जो पहले कभी जम्मू और कश्मीर में होता रहा है। उन्हीं खानदानी नेताओं का सहारा लेकर वांगचुक भी लद्दाख में ऐसा ही बड़ा करने की फिराक में थे जिससे लद्दाख के मूल निवासी पलायन को मजबूर हो सकें और बाहरी घुसपैठियों को संरक्षण देकर फिर लद्दाख को भी जम्मू काश्मीर की तरह पाकिस्तान का अंग बताने का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बनाकर भारत की अखंडता, संप्रभुता को खतरा पैदा करने के मनसूबे थे। परन्तु सोनम वांगचुक की यह षड्यंत्रकारी कूटनीति सामने आने से उनके और उनके आकाओं के सपनों पर अब पानी फिर गया है।

विदेशी फंडिंग पर केन्द्र ने सख्त पाबंदी लगा दी हैं। संभवतः जल्दी ही सोनम वांगचुक असंवैधानिक गतिविधियों को लेकर जेल के सलाखों के पीछे भी नजर आ सकते हैं। वांगचुक को बढ़ावा देने वाले तथाकथित चेहरे भी जल्दी ही सामने आएंगे। जेन जी की आड़ में आगजनी, तोड़फोड़, राष्ट्रीय सम्पत्तियों का भारी नुकसान करना राष्ट्र द्रोह के तहत कानूनी कार्रवाई करने पर अन्य लोगों को भी सख्त सबक भी मिलेगा।

वांगचुक चाहे जितना सोसियल एक्टिविस्ट का चोला ओढ़कर आम जनता को गुमराह करने की लाख कोशिशें कर लें परन्तु अब जांच एजेंसियों ने भी कसकर कमर कस ली है। आंदोलन औल घटनाओं को अंजाम देने में जो नेपाली लड़के पकड़े गए हैं वे सब घुसपैठियों की शक्ल में लद्दाख में भविष्य में और भी बड़ी संख्या में पैर जमाने की कोशिश में लगे हुए थे। इससे साफ जाहिर होता है कि वांगचुक विदेशी ताकतों के साथ मिलकर बंगलादेशी घुसपैठियों को नये ढंग से बसाने की पूरजोर कोशिश जारी थी। इधर केन्द्र सरकार हर राज्यों से बंगलादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने में रात दिन सख्ती से जुटीं हुई है और उधर वांगचुक जैसे लोग समाज सेवा की आड़ में देश में एक नई क्रांति को जन्म देने विदेशी फंडिंग के सहारे देश की एकता, अखंडता,संप्रभुता और सामाजिक ताने-बाने के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहें हैं।अब वांगचुक का अंजाम क्या होगा यह तो आने वाला समय ही बतायेगा कि वांगचुक का विदेशी फंडिंग का लाइसेंस रद्द होने के बाद और अब भविष्य में वांगचुक के देश में देश के बाहर के आकाओं की गतिविधियों से क्या क्या नुकसान हो सकता था !

आक्रोश के नाम पर जहर उगल रहे विपक्षी

सोनम वांगचुक को जो नेता कभी व्यक्तिगत मिले नहीं वे आज मीडिया में उसका समर्थन कर बड़ी बड़ी डिंगे मार रहें हैं।यह कैसी राजनीति का खेल है कि देश की संप्रभुता को दरकिनार कर केवल राजनीतिक लाभ की खातिर कुछ भी बोलना एक फैशन सा चल पड़ा है। टीवी मीडिया ने ऐसे चेहरों को ज्यादा तवज्जों भी नहीं देना चाहिए। ऐसे नेताओं को किसी चर्चा या भाषण में सुनना भी अच्छी भली मानसिकता को खराब करना है। कुछ नेताओं के बयान है कि लद्दाख को स्वतंत्र राज्य का दर्जा ना दिए जाने से वहा कि जनता में तीव्र आक्रोश था । यह बात बिल्कुल सरासर गलत गहराई जा रही है।आम जनता शांति से अपने उद्यम और रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हैं परन्तु जो भाड़े के घुसपैठिए थे वे अंदर अंदर ही चिनगारी लगाने में जुटें हुए थे यह बात जांच पड़ताल में भी सामने आ चुकी है कि काश्मीर को फिर से जलानें का काम वांगचुक जैसे तथा कथित समाजसेवियों, नेताओं,पडौसी देशों के मोदी विरोधियों और देश के अंदर के कुछ दलों के नेताओं ने मोदी को सीधे हरा ना पाने की निराशा हताशा में देश की संप्रभुता एकता अखंडता और विकास को तोड़ने की अप्रत्यक्ष कोशिशें आरंभ कर दी है।

अब देखना यह है कि भविष्य में मोदी के। तमाम विरोधियों को कैसे,कब उल्टे मुंह की खाना पड़ेगी यह। जल्दी ही हम सब को भी पता चल जाएगा।

विश्व पर्यटकों के लिये अनंत संभावनाओं का देश है भारत

विश्व पर्यटन दिवस- 27 सितम्बर, 2025 इस बात का स्मरण कराता है कि पर्यटन केवल मनोरंजन का साधन भर नहीं है, बल्कि यह किसी भी राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति का आधार स्तंभ है। इस वर्ष की थीम कुछ स्रोतों में पर्यटन और हरित निवेश या पर्यटन और सतत परिवर्तन बतायी जा रही है जिसका उद्देश्य पर्यटन को स्थिरता और समावेशिता के साथ बढ़ावा देना है। यह थीम स्थायी पर्यटन के लिए हरित निवेश की तत्काल आवश्यकता पर जोर देती है, जो समुदायों और ग्रह दोनों के लिए फायदेमंद है। जिसके माध्यम से, पर्यटन में वैश्विक सहयोग और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें हरित निवेश, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरणीय दुष्प्रभाव को कम करना शामिल है। यह दिवस मनाते हुए भारत की पर्यटन संभावनाओं पर चिन्तन-मंथन करना जरूरी है। क्योंकि भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में पर्यटन की संभावनाएं अनंत हैं। यहाँ हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर गोवा और अंडमान के समुद्र तटों तक, काशी और बोधगया की आध्यात्मिक आभा से लेकर अजमेर और पुष्कर की आस्था तक, केरल के बैकवाटर्स से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान तक हर अनुभव अपने आप में अद्वितीय है। यही कारण है कि भारत का पर्यटन उद्योग आज नई उड़ान भर रहा है और वैश्विक मानचित्र पर अपनी पहचान बना रहा है।

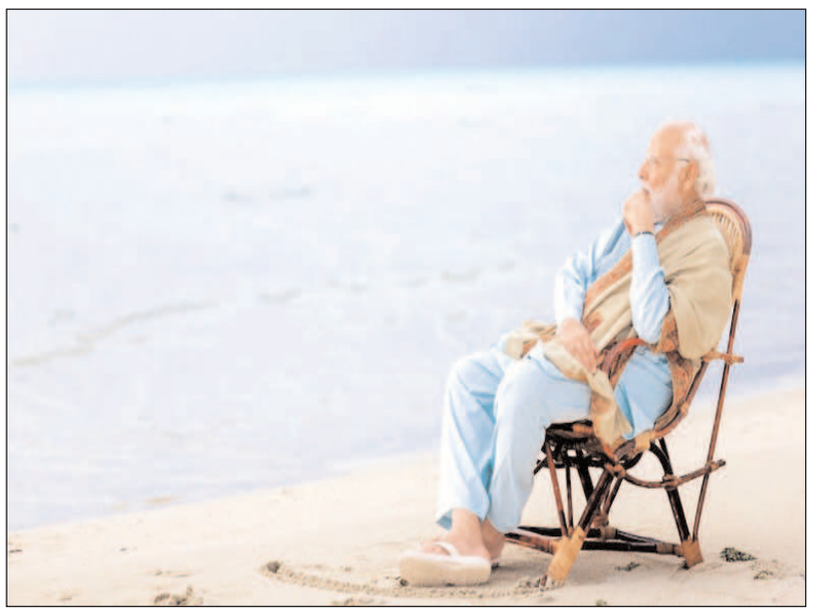

विश्व पर्यटन दिवस दुनिया के प्रमुख पर्यटन स्थलों की यात्रा के लिये तो आमंत्रित करता ही है, लेकिन भारत की विविधता और बहुसंस्कृतिवाद के कारण दुनिया के पर्यटकों के लिये विशेष आकर्षक का केन्द्र बन रहा है। जो जीवन में खुशियां एवं मुस्कान देने वाले पर्यटन के महत्व को उजागर भी करता है। आर्थिक विकास और सांस्कृतिक कूटनीति को बेहतर बनाने के लिए पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने की पहल बदलते समय के साथ विश्व पर्यटन दिवस नई पहलों, नीतिगत सुधारों और क्षेत्र की उपलब्धियों का जश्न मनाने पर ध्यान केंद्रित करने वाले दिन के रूप में विकसित हुआ है। इसका उद्देश्य रोजगार सृजन, विश्व मानवता को बल देना, युद्धमुक्त वातावरण और विविध वैश्विक सांस्कृतिक विरासत और डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देकर विश्व समुदायों को सशक्त बनाना है। भारत में पर्यटन के आर्थिक प्रभाव बेहद व्यापक हैं। यह भारत की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देता है और करोड़ों लोगों के लिए रोजगार का सबसे बड़ा साधन बन चुका है। गाँवों और कस्बों तक पर्यटन का असर पहुँच रहा है, जिससे स्थानीय हस्तशिल्प, लोककला और खानपान को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिल रही है। विदेशी पर्यटक न केवल हमारी संस्कृति और आध्यात्मिकता से प्रभावित होते हैं। पर्यटन के सामाजिक प्रभाव भी उल्लेखनीय हैं। यह सांस्कृतिक आदान-प्रदान का माध्यम बनकर विभिन्न धर्मों, भाषाओं और परंपराओं के बीच सद्भाव और भाईचारे को बढ़ाता है। महिला सशक्तिकरण और युवा उद्यमिता को पर्यटन ने नया आयाम दिया है। होम-स्टे, गाइडिंग, हस्तशिल्प और लोक-कलाओं में महिलाओं और युवाओं की सक्रिय भागीदारी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है। यही नहीं, ग्रामीण पर्यटन ने गाँवों को विकास के नए अवसर प्रदान किए हैं और पलायन की समस्या को कम करने की क्षमता दिखाई है।

राजनीतिक और अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से भी पर्यटन भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत करता है। इनक्रेडिबल इंडिया और देखो अपना देश जैसे अभियानों ने भारत की वैश्विक पहचान को और गहरी किया है। हाल के वर्षों में भारत ने जी-20 जैसे आयोजनों के जरिए अपने पर्यटन स्थलों की भव्यता और सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, जिससे न केवल राजनीतिक विश्वास बढ़ा बल्कि भारत की सांस्कृतिक शक्ति का विस्तार भी हुआ। पड़ोसी देशों के साथ बौद्ध और आध्यात्मिक सर्किट की योजनाओं ने भारत को एशिया का आध्यात्मिक केंद्र स्थापित करने में मदद की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यटन को भारत की शक्ति बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा, देखो अपना देश अभियान और प्रोजेक्ट आध्यात्मिक सर्किट जैसी योजनाओं के माध्यम से पर्यटन को जन-आंदोलन का रूप दिया है।

योग और आयुर्वेद को विश्वभर में लोकप्रिय बनाने के उनके प्रयासों ने भारत को हेल्थ और वेलनेस टूरिज्म का प्रमुख केंद्र बना दिया है। मोदी सरकार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, हवाई अड्डों का विस्तार, चारधाम परियोजना, उच्च गति रेल और भारतमाला जैसी योजनाएं पर्यटन को नई सुविधाओं से जोड़ रही हैं। प्रधानमंत्री का यह मानना है कि भारत का हर गाँव और हर शहर अपने आप में एक अनोखा पर्यटन स्थल है और उसकी कहानी दुनिया तक पहुँचाई जानी चाहिए। आज जब डिजिटलाइजेशन ने पर्यटन को नई दिशा दी है, ऑनलाइन टिकटिंग, वर्चुअल टूर और एआई आधारित यात्रा मार्गदर्शन ने पर्यटन को आधुनिक युग से जोड़ दिया है। सस्टेनेबल टूरिज्म पर जोर देकर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रकृति और संस्कृति दोनों की सुरक्षा बनी रहे। मिलेनियल्स और नई पीढ़ी अनुभव-आधारित और साहसिक पर्यटन की ओर आकर्षित हो रही है और भारत इस अवसर को भुनाने में आगे बढ़ रहा है। भारत विश्व स्तर पर पांचवां सबसे बड़ा यात्रा और पर्यटन बाजार बनने के लिए तैयार है। भारत में पर्यटन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और 2027 तक तीसरा सबसे बड़ा घरेलू बाजार बनने की उम्मीद है। 2023 में, भारत में पर्यटन पर होने वाला खर्च 2019 के 127 बिलियन डॉलर से बढ़कर 174 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया। सबसे ज्यादा पर्यटक तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र सहित 5 राज्यों में गए, जहाँ कुल मिलाकर 65 प्रतिशत पर्यटक आए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शिता से धार्मिक पर्यटन को नये पंख लगे हैं, अयोध्या में बना भगवान श्रीराम का मन्दिर एवं प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ ने धार्मिक पर्यटन के नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं। धार्मिक पर्यटन आर्थिक उन्नति और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

संवाद से समाधान तक: लेह-लद्दाख में हिंसा का सबक

ललित गर्ग

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को राज्य का दर्जा देने व संविधान के अंतर्गत विशेष संरक्षण देने वाली छठी अनुसूची में शामिल करने के लिये चल रहे आंदोलन का हिंसक एवं विध्वंसक होना, विरोध प्रदर्शन, पुलिस के साथ झड़प और आगजनी की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण होने के साथ-साथ चिन्ताजनक है। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी एकत्र हुए और उन्होंने लेह में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आग लगा दी और उसके बाहर खड़े वाहनों को फूंक दिया। आमतौर पर बेहद शांत रहने वाले लद्दाख के लिए यह बहुत बड़ी घटना है। दरअसल, पर्यावरणविद् और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक दो सप्ताह से अनशन पर थे, उनके साथ अन्य कार्यकर्ता भी अनशनरत थे, जिनकी तबीयत बिगड़ने से जन-आक्रोश एवं हिंसा भड़की। इस हिंसा ने अनेक सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर यह घटना वहाँ की जनता के असंतोष और बेचैनी को उजागर करती है, वहीं दूसरी ओर यह संकेत देती है कि लंबे समय से किए जा रहे वादे और आश्वासन क्यों अधूरे रह गए और क्यों स्थानीय लोग स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं?

सरकार ने अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 और 35ए के प्रावधान हटाने के साथ ही जम्मू-कश्मीर से अलग कर लद्दाख को केंद्र शासित राज्य बनाया था। तब सरकार ने वादा किया था कि हालात सामान्य होते ही पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। लोगों ने सोचा था कि अब उनकी पहचान, संस्कृति और स्थानीय अधिकार और अधिक सुरक्षित होंगे। लेकिन इसके विपरीत उनकी आशंकाएँ बढ़ीं। उन्हें लगा कि संघ शासित प्रदेश के रूप में दिल्ली से संचालित प्रशासन स्थानीय जरूरतों और आकांक्षाओं को समझने और पूरा करने में असफल हो रहा है। इसी कारण 6 साल बाद लोगों का भरोसा और सब्र डगमगाने लगा। इसी के चलते सोनम वांगचुक को अहिंसक आन्दोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ा, जो कतिपय कारणों से हिंसक हो गया। हालांकि, हिंसा के बाद वांगचुक ने अपना अनशन त्याग कर आंदोलनकारियों से शांति की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की हिंसा से शांतिपूर्ण आंदोलन का मेरा संदेश आज विफल हो गया। अगर युवा गलत रास्ते पर जाएंगे, तो इससे हमारे वास्तविक उद्देश्य गुम हो जायेंगे। वाकई, लद्दाख के संयमी समाज को सतर्कता और संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। वांगचुक का पूरा आंदोलन अहिंसक रहा है। सरकार से मतभेद होने पर भी उन्होंने बातचीत का रास्ता नहीं छोड़ा। उनके समर्थन में खड़े युवाओं को इसे समझना चाहिए। हिंसा से समस्या जटिल हो जाएगी। लद्दाख की जो भौगोलिक स्थिति है, उसे देखते हुए वहां के लोगों को कानून-व्यवस्था के प्रति विशेष रूप से सजग रहना चाहिए। लद्दाख का केंद्रशासित प्रदेश बनना एक नये सूरज का उदय होना है और इसका वहां के लोगों ने स्वागत भी किया था। इस क्षेत्र को कश्मीर घाटी के वर्चस्व से मुक्ति मिली थी, पर वहां के लोगों की महत्वाकांक्षा को राजनीति रंग देकर एवं संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के अंधेरों में धकेल कर इसके वास्तविक उद्देश्यों को धुंधलाने की कुचेष्टा की गई है।

हिंसा व आगजनी के बाद केंद्र शासित प्रदेश में संचारबंदी लागू की गई है। मीडिया माध्यमों से कुछ आंदोलनकारियों के मारे जाने की बात भी कही जा रही है। प्रतिक्रिया स्वरूप लेह बंद का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। यह प्रदर्शन कालांतर हिंसक प्रतिरोध में बदल गया। घटनाक्रम के बाद जम्मू-कश्मीर के विपक्षी दलों ने हिंसा के लिये केंद्र को निशाने पर लिया है। कहा गया कि आंदोलनकारी लेह की अस्मिता को संरक्षण देने और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्र व लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच आगामी 6 अक्टूबर, 2025 को एक वार्ता का दौर निर्धारित था, जिसमें लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के सदस्य शामिल होने वाले हैं।

जब बातचीत होने ही वाली है, तो ऐसे विरोध प्रदर्शन की क्या जरूरत थी? लेह के लोग अधूरे वायदों से खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उनमें यह डर है कि अगर शासन उनके हाथ में न रहा तो प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन होगा। इसी वजह से आंदोलनकारियों की हिंसक अभिव्यक्ति सामने आई है। वास्तव में, यह पूरा आंदोलन राजनीतिक प्रवृत्ति का है।

नेपाल में माओवादी पार्टी की केंद्रीय समिति भंग, प्रचंड ने छोड़ा अध्यक्ष पद

काठमांडू। नेपाल में 8 और 9 सितंबर को हुए युवाओं के आंदोलन का असर राजनीतिक दलों पर दिखने लगा है। राजनीतिक दलों में नेतृत्व परिवर्तन की मांग के बाद माओवादी पार्टी की केंद्रीय समिति को भंग कर दिया गया है। अब नए नेतृत्व के लिए दिसंबर में पार्टी का विशेष महाधिवेशन बुलाया गया है। काठमांडू में आज पार्टी की सातवीं केंद्रीय समिति की बैठक के दौरान यह कदम पार्टी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचंड के प्रस्ताव के बाद उठाया गया है। केंद्रीय समिति की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रचंड ने कहा कि समिति को भंग कर दिया गया है। प्रस्ताव के अनुसार पार्टी दिसंबर में एक विशेष सम्मेलन बुलाएगी। बैठक में प्रचंड के समन्वय के तहत एक सम्मेलन आयोजन समिति बनाने का भी निर्णय लिया गया। केंद्रीय समिति भंग करने के बाद प्रचंड ने कहा है कि वह अब माओवादी के अध्यक्ष नहीं हैं, लेकिन अब पार्टी की विशेष सम्मेलन आयोजन समिति के समन्वयक के रूप में कार्य करेंगे।

एफबीआई के पूर्व निदेशक कॉमी मुश्किल में फंसे, अमेरिकी कांग्रेस से झूठ बोलने का आरोप

वाशिंगटन। अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी (एफबीआई) के पूर्व निदेशक जेम्स कॉमी पर कांग्रेस से झूठ बोलने का आरोप लगा है। यह आपराधिक मामला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अपने अटॉर्नी जनरल से पूर्व एफबीआई निदेशक कॉमी और उनके अन्य राजनीतिक विरोधियों पर मुकदमा चलाने का आग्रह करने के कुछ दिनों बाद दायर किया गया। इस अभियोग के साथ कॉमी, ट्रंप की प्रमुख शिकायतों में से एक, 2016 के चुनाव में रूसी हस्तक्षेप की लंबे समय से चल रही जांच में शामिल होने वाले पहले पूर्व वरिष्ठ सरकारी अधिकारी बन गए हैं, जिन पर मुकदमा चलाया जाएगा। ट्रंप वर्षों से इस जांच को धोखा और जासूसी बताते रहे हैं, जबकि कई सरकारी समीक्षाओं में यह दिखाया गया है कि मॉस्को ने रिपब्लिकन के अभियान में हस्तक्षेप किया था। इस आपराधिक मामले से यह चिंता और गहरा सकती है कि अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी के अधीन न्याय विभाग को उन सार्वजनिक हस्तियों की जांच और अब उन पर मुकदमा चलाने के लिए हथियार बनाया जा रहा है, जिन्हें राष्ट्रपति अपने राजनीतिक दुश्मन मानते हैं। ट्रंप ने गुरुवार को अभियोग को अमेरिका के लिए न्याय करार दिया। ट्रंप के वफादार बॉन्डी और रूसी जांच के लंबे समय से मुखर आलोचक रहे एफबीआई निदेशक काश पटेल ने भी इसी तरह के बयान जारी किए। बॉन्डी ने कहा, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।

दक्षिण कोरिया में हुए गैस विस्फोट दुर्घटना में 28 लोग घायल

सियोल। दक्षिण कोरिया में शनिवार को हुई गैस विस्फोट दुर्घटना में 28 लोग घायल हो गए। यह जानकारी समाचार एजेंसी ने दी। यह विस्फोट स्थानीय समयानुसार सुबह लगभग 10:17 बजे (0117 जीएमटी) ग्योंगगी प्रांत के यांगजू में एक सूखे वाष्पकक्ष में हुआ। घायलों में ग्राहक और कर्मचारी दोनों शामिल हैं, जिनमें से तीन की हालत गंभीर है। विस्फोट के कारण आग तो नहीं लगी लेकिन दर्जनों ग्राहकों को बाहर निकलना पड़ा। अग्निशमन अधिकारियों ने बचाव कार्य के लिए 42 कर्मियों और 17 उपकरणों को भेजा। अधिकारी दुर्घटना के वास्तविक कारण की जांच कर रहे हैं।

हाइको और जकार्ता को जोड़ने वाला नया हवाई मार्ग आधिकारिक तौर पर खोला गया

जकार्ता। चीन के हैनान प्रांत की राजधानी हाइको को इंडोनेशिया के सबसे बड़े शहर जकार्ता से जोड़ने वाले सीधे उड़ान मार्ग का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया गया, जिससे दोनों देशों के बीच संपर्क को मजबूती मिलेगी। हवाई मार्ग के उद्घाटन के बाद हैनान एयरलाइंस द्वारा संचालित उड़ान हाइको मीलान अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हुई और चार घंटे से अधिक की यात्रा के बाद स्थानीय समयानुसार शाम लगभग 6:10 बजे जकार्ता के पास बांतेन प्रांत के सोएकरनो-हट्टा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी। उड़ान के आगमन पर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया जिसमें इंडोनेशिया के सरकारी अधिकारी, चीनी राजनयिक और हवाई अड्डे के प्रतिनिधि शामिल हुए। यात्रियों का स्वागत सांस्कृतिक कार्यक्रमों और स्मृति चिह्नों के साथ किया गया। इंडोनेशिया में चीन के राजदूत वांग लुटोंग ने अपने संबोधन में कहा कि दोनों राष्ट्राध्यक्षों के रणनीतिक मार्गदर्शन में चीन-इंडोनेशिया संबंधों का सुदृढ़ और स्थिर विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि लोगों के बीच आदान-प्रदान द्विपक्षीय सहयोग के 'पाँच स्तंभों' का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

श्री वांग ने कहा, चीन इंडोनेशिया में विदेशी पर्यटकों का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है, जबकि इंडोनेशिया चीनी यात्रियों के लिए शीर्ष विदेशी गंतव्यों में से एक बना हुआ है। नई सीधी उड़ान की शुरुआत से लोगों की आवाजाही आसान होगी और दोनों देशों के बीच पर्यटन तथा सांस्कृतिक सहयोग को और बढ़ावा मिलेगा।

विश्व व्यापार को मिल रही चुनौतियों का मुकाबला करे ब्रिक्स : एस. जयशंकर

एजेंसी

संयुक्त राष्ट्र । उन्होंने कहा कि बढ़ते संरक्षणवाद, ऊंचे-नीचे शुल्क और गैर-शुल्क बाधाएं व्यापार को प्रभावित कर रही हैं, ऐसे में ब्रिक्स को बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने यह बात ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में कही। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही धमकी दी थी कि ब्रिक्स देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। इसके अलावा, उन्होंने अन्य आधारों पर भारत और ब्राजील पर कुल 50 प्रतिशत और दक्षिण अफ्रीका से होने वाले अधिकांश आयातों पर 30 प्रतिशत टैरिफ लगाया है।हालांकि जयशंकर ने अपने बयान में अमेरिका का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया। बैठक में भाग लेने वाले इथियोपिया के विदेश राज्य मंत्री हदेरा अबेरा अदमासु ने भी संयुक्त कार्रवाई का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को शांति

स्थापित करने, वैश्विक संस्थाओं में सुधार लाने और विकासशील देशों के लिए न्यायपूर्ण व सुरक्षित माहौल बनाने में अहम भूमिका निभानी चाहिए।जयशंकर ने यह भी कहा कि जब बहुपक्षीय व्यवस्था दबाव में है, तब ब्रिक्स ने हमेशा विवेकपूर्ण और सकारात्मक बदलाव की आवाज उठाई है। उन्होंने आईबीएसए (भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका का समूह) के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी हिस्सा लिया। उन्होंने 'एक्स' पर लिखा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की जरूरत पर जोर दिया गया। साथ ही आईबीएसए के शैक्षणिक मंच, समुद्री अभ्यास, ट्रस्ट फंड और आपसी व्यापार पर चर्चा हुई। ब्रिक्स मंत्रियों की बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुधारों पर भी चर्चा हुई। जयशंकर ने मंत्रियों से कहा, व्यापार प्रणाली से परे, ब्रिक्स को संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों, विशेष रूप से सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार के लिए भी जोरदार प्रयास करना चाहिए।' उन्होंने कहा, 'एक अशांत विश्व में, ब्रिक्स को शांति स्थापना, संवाद, कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन के संदेश को सुदृढ़ करना चाहिए।' ब्रिक्स एक संगठन है जिसका नाम इसके पहले पांच सदस्य देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के शुरुआती अक्षरों से बना है।

ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट ने चार अरब डॉलर की विदेशी सहायता राशि रोकने की अनुमति दी

एजेंसी

वाशिंगटन। अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन को कांग्रेस से आवंटित विदेशी सहायता पर चार अरब डॉलर के खर्च को रोकने की अनुमति दे दी। इससे पहले एक संघीय न्यायाधीश ने फैसला सुनाया था कि प्रशासन को महीने के अंत तक यह धनराशि खर्च करनी होगी। उच्चतम न्यायालय के फैसले ने इस पर रोक लगा दी। एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पब्लिक सिटीजन लिटिगेशन ग्रुप के वकील निकोलस सैंसोम ने कहा, यह परिणाम शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांतों को और कमजोर करता है। इसका गंभीर मानवीय प्रभाव भी पड़ेगा। निकोलस सैंसोम मुकदमा दायर करने वाले गैर-लाभकारी समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। न्यायालय ने संक्षिप्त आदेश में कहा कि सरकार ने पर्याप्त रूप से साबित कर दिया है कि जिन समूहों ने मुकदमा दायर किया, उन्हें इम्पाउंडमेंट कंट्रोल एक्ट नामक कानून के तहत संबंधित मुकदमा दायर करने से रोक दिया गया उल्लेखनीय है कि जनवरी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद से न्यायालय ने प्रशासन के 20 आपातकालीन आवेदनों को स्वीकार कर लिया है। आपातकालीन आवेदनों की संख्या और जिस दर से न्यायालय ने प्रशासन के पक्ष में फैसला सुनाया है, दोनों ही अभूतपूर्व हैं। बाद वाले आवेदन ने निचली अदालत के न्यायाधीशों सहित कानूनी समुदाय के भीतर आलोचना को जन्म दिया है। न्यायालय में तीन उदारवादियों ने असहमति जताई। न्यायमूर्ति एलेना कगन ने लिखा कि इस मामले में कानूनी मुद्दा पहले कभी प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसका अर्थ है कि अदालत अज्ञात क्षेत्र में काम कर रही थी। उन्होंने कहा कि फिर भी, बहुमत ने मौखिक दलीलें सुने बिना या पूरी तरह से तर्कसंगत निर्णय दिए।

जयशंकर ने कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ मुलाकात में आपसी रिश्तों की मजबूती पर दिया जोर

एजेंसी

संयुक्त राष्ट्र । विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र के दौरान कई देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इन मुलाकातों का उद्देश्य भारत के रिश्तों को और मजबूत करना और अलग-अलग देशों के वैश्विक दृष्टिकोण को समझना था। जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों, यूक्रेन संघर्ष और पश्चिम एशिया की स्थिति पर बातचीत की। संयुक्त अरब अमीरात के उपप्रधानमंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से उन्होंने दोनों देशों के सहयोग और होने वाली संयुक्त आयोग बैठक की तैयारियों पर चर्चा की। जयशंकर ने कहा कि उन्हें उनके विचार मौजूदा वैश्विक हालात पर उपयोगी लगे। ऑस्ट्रिया की विदेश मंत्री बीट माइनल-राइजिंगर ने मुलाकात के बाद जयशंकर को धन्यवाद दिया और कहा कि भारत और ऑस्ट्रिया की साझेदारी को मजबूत करना दोनों देशों के साथ-साथ यूरोप के लिए भी लाभकारी है। जयशंकर ने बताया कि उन्होंने भारत और यूरोप के सामने मौजूद चुनौतियों और अवसरों

पर गहन चर्चा की। इसके अलावा जयशंकर ने एंटीगुआ-बारबुडा, उरुग्वे, इंडोनेशिया, सिएरा लियोन और रोमानिया के विदेश मंत्रियों से भी मुलाकात की। भारत-सीईएलएसी बैठक की सह-अध्यक्षता कोलंबिया की विदेश मंत्री रोजा योलांडा विलाविसेनियो के साथ करते हुए, जयशंकर ने 'एक्स' पर कहा कि वे 'वैश्विक दक्षिण की आवाज का बेहतर प्रतिनिधित्व करने के लिए बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार की तत्काल आवश्यकता' पर सहमत हैं। बैठक में कृषि, व्यापार, स्वास्थ्य, डिजिटल तकनीक, आपदा राहत और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। उन्होंने आगे कहा कि वे एआई, प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिजों, अंतरिक्ष और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी सहमत हुए।

हूती ने लाल सागर में जहाज पर हमला किया, पाकिस्तान के 24 नागरिक हैं चालक दल में

एजेंसी

सना (यमन)। ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों ने ईरानी बंदरगाह बंदर अब्बास से यमन पहुंचे तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) से लदे एक जहाज पर हमला किया है। इस जहाज में कप्तान और चालक दल के सभी 24 सदस्य फिलहाल संकट में हैं, मगर सुरक्षित हैं। यह सभी पाकिस्तान के नागरिक हैं। राजनयिक सूत्रों ने इसकी पुष्टि की। पाकिस्तान के समाचार पत्र द न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार,राजनयिक सूत्रों ने कहा कि यह जहाज इस समय यमन सरकार के नियंत्रण वाले क्षेत्र में नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। एक वीडियो संदेश में चालक दल ने बताया कि 10 दिन पहले यमन के बंदरगाह पर हुए ड्रोन हमले में उनके जहाज को निशाना बनाया गया। तब से यह जहाज बंदरगाह में फंसा हुआ है। जहाज के कप्तान ने जिबूती जाने की तत्काल अनुमति मांगी है। चालक दल ने कहा कि वे पाकिस्तान के समुद्री मामलों के मंत्रालय और बंदरगाह महानिदेशक से सहायता का इंतजार

कर रहे हैं। चालक दल ने दावा किया कि हूती लड़ाके जहाज पर मौजूद हैं और पाकिस्तानी चालक दल को उतरने नहीं दे रहे हैं। उल्लेखनीय है कि यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोही सक्रिय हैं। वह लाल सागर में जहाजों और युद्धपोतों को निशाना बनाते रहते हैं। हूती सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल यह्या सारी ने जून में एक रिकॉर्डेड वीडियो बयान में कहा था, यदि अमेरिका, इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर आक्रमण और हमले में शामिल होता है, तो हमारी सशस्त्र सेनाएं लाल सागर में उसके जहाजों और युद्धपोतों को निशाना बनाएंगी। हूती विद्रोही इजराइल-गाजा संघर्ष शुरू होने के बाद हमास के समर्थन में लाल सागर में डेरा डाला हुआ है। लाल सागर अंतरराष्ट्रीय नौवहन का एक प्रमुख मार्ग है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ईरान परमाणु समझौते के विस्तार पर प्रस्ताव पारित करने में विफल

एजेंसी

संयुक्त राष्ट्र । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद उस प्रस्ताव को पारित करने में विफल रही, जिसमें ईरान के परमाणु समझौते (2015) को छह महीने और बढ़ाने की बात थी। इसका मकसद था कि कूटनीति को और समय मिल सके।

अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता तो ईरान और छह देशों (ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और अमेरिका) के बीच हुआ परमाणु समझौता छह महीने और जारी रहता। इसके साथ ही सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 2231 भी छह महीने और आगे बढ़ जाता। इसे अपनाने से ईरान पर लगे संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध तुरंत वापस लागू नहीं हो पाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वोटिंग का नतीजा 19 सितंबर को हुए एक और प्रस्ताव जैसा ही रहा था, जिसे दक्षिण कोरिया ने रखा था। तब भी यही परिणाम निकला

था और ईरान को प्रतिबंधों से राहत नहीं मिल सकी थी। अल्जीरिया, चीन, पाकिस्तान और रूस ने मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। गुयाना और कोरिया गणराज्य ने मतदान में भाग नहीं लिया। सुरक्षा परिषद के शेष नौ सदस्यों ने इसके विरुद्ध मतदान किया। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी का कहना है कि उन्होंने 28 अगस्त को सुरक्षा परिषद को सूचना देकर स्नैपबैक प्रक्रिया शुरू कर दी है, क्योंकि ईरान समझौते की शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 2231 के तहत, इस सूचना के 30 दिन बाद वे सारे प्रतिबंध अपने आप फिर से लागू हो जाते हैं जो इस प्रस्ताव के आने से पहले ईरान पर लगे थे। हालांकि, इन तीन देशों के कदम की वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने जेसीपीओए और रेजोल्यूशन 2231 में दिए गए विवाद समाधान तंत्र (डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म) को पूरा नहीं किया है। जेसीपीओए और रेजोल्यूशन 2231 के तहत, विवाद समाधान तंत्र को किसी भी असहमति को हल करने के लिए 35 दिन मिलते हैं। उसके बाद ही स्नैपबैक की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। प्रस्ताव 2231 की समयसीमा 18 अक्टूबर 2025 को समाप्त होगी। उसके बाद सुरक्षा परिषद ईरान परमाणु समझौते पर विचार करना बंद कर देगी।

अमेरिकी न्याय विभाग ने जिला अटॉर्नी फानी विलिस का यात्रा संबंधी रिकॉर्ड तलब किया

एजेंसी

अटलांटा (जॉर्जिया)। अमेरिकी न्याय विभाग ने संघीय ग्रैंड जूरी समन जारी कर फुल्टन काउंटी की जिला अटॉर्नी फानी विलिस का यात्रा संबंधी रिकॉर्ड तलब किया है। फानी ने चुनाव में हस्तक्षेप को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आपराधिक मामला दायर किया था। संघीय जांच का उद्देश्य पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। यह भी साफ नहीं है कि विलिस जांच का केंद्र हैं या उन पर आरोप लग सकते हैं। लेकिन समन से संकेत मिलता है कि राष्ट्रपति ट्रंप के अधीन न्याय विभाग अपना ध्यान उनके सबसे मुखर कानूनी विरोधियों में से एक पर केंद्रित कर सकता है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने प्रकाशित एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया है। रिपोर्ट के अनुसार, संघीय जांचकर्ता 2024 में चुनाव के समय विलिस की संभावित अंतरराष्ट्रीय यात्राओं के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। इस जांच का नेतृत्व जॉर्जिया के उत्तरी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी थियोडोर हर्ट्जबर्ग कर रहे हैं। फुल्टन काउंटी में ट्रंप और उनके कई सहयोगियों पर जॉर्जिया के 2020 के चुनाव परिणाम को पलटने के उनके प्रयासों के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है। एक अदालत ने फानी को इस मामले से हटा दिया था। अदालत को पता चला था कि विशेष अभियोजक नाथन वेड के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे। बचाव पक्ष के वकीलों ने उन पर ट्रंप द्वारा भुगतान की गई यात्राओं से लाभ उठाने का आरोप लगाया है। ये यात्राएं 2022 और 2023 में हुईं। पिछले हफ्ते ही जॉर्जिया के उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट ऑफ जॉर्जिया) ने निचली अदालत के उस फैसले की समीक्षा करने से इनकार कर दिया था, जिसमें विलिस को ट्रंप और उनके आठ सह-प्रतिवादियों के खिलाफ 2020 के चुनाव अभियोजन से अयोग्य घोषित किया गया था।

किम जोंग उन ने परमाणु शक्ति पर दोहराया अपना 'अपरिवर्तनीय' रुख, कहा- देश की सुरक्षा के लिए जरूरी

एजेंसी

सियोल । उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन ने फिर दोहराया है कि उनका देश अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियारों पर ही भरोसा करता रहेगा। उन्होंने कहा कि परमाणु ताकत बनाए रखना और उसे और मजबूत करना उनके देश का सबसे अहम और पहला काम है। उनका यह संदेश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा उत्तर कोरिया के 'पूर्ण' परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि किए जाने के बाद आया है। बैठक में, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश के परमाणु रुख को आगे बढ़ाने के लिए सतत तैयारी करना एक 'आवश्यक सर्वोच्च प्राथमिकता वाला कार्य' है, और इसे 'अपरिवर्तनीय कर्तव्य' बताया।

किम ने साफ़ किया कि परमाणु शक्ति ही उत्तर कोरिया की असली

ढाल और तलवार है, जो देश की संप्रभुता और सुरक्षा की गारंटी देती है। केसीएनए ने कहा कि किम ने संतोष जताया कि देश की परमाणु क्षमता बढ़ाने के लिए जरूरी अहम काम पूरे किए जा चुके हैं। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि वे काम कौन से हैं। हाल ही में हुई बैठक में पार्टी के एक प्रमुख वरिष्ठ अधिकारी होंग सुंग-मू ने भाग लिया, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम का नेतृत्व किया था। किम ने हाल ही में संसद में दिए भाषण में यह भी कहा कि उत्तर कोरिया अमेरिका से बातचीत करने को तैयार है, लेकिन तभी जब अमेरिका परमाणु हथियार छोड़ने की शर्त हटाए। उन्होंने दोहराया कि उत्तर कोरिया कभी भी परमाणु हथियारों से समझौता नहीं करेगा, और इस बात पर जोर दिया कि परमाणु शक्ति के रूप में उत्तर कोरिया को 'अपरिवर्तनीय' स्थिति देश के संविधान में निहित है। दक्षिण कोरिया के एक मंत्री के अनुसार, उत्तर कोरिया के पास लगभग 2000 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम होने का अनुमान है और वह चार अलग-अलग जगहों पर यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज चला रहा है ताकि परमाणु सामग्री इकट्ठी की जा सके।

समाचार एजेंसी ने कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (केसीएनए) के हवाले से बताया कि किम ने यह टिप्पणी उस समय की जब उन्होंने परमाणु वैज्ञानिकों और तकनीशियनों से मुलाकात की और परमाणु सामग्री एवं हथियारों के उत्पादन पर एक महत्वपूर्ण परामर्श बैठक की अध्यक्षता की।

हंगरी ने जेलेंस्की के ड्रोन से हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के दावे को किया खारिज

एजेंसी

बुडापेस्ट । हंगरी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के इस दावे को खारिज कर दिया कि हंगरी के जासूसी ड्रोन ने यूक्रेन के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया होगा। हंगरी के विदेश और व्यापार मंत्री पीटर सिज्जार्टो ने इस आरोप को दृढ़ता से खारिज कर दिया है। सिज्जार्टो ने फेसबुक पेज पर लिखते हुए कहा कि जेलेंस्की हंगरी विरोधी भावनाओं में खो गए हैं और फालतू बातों के पीछे भाग रहे हैं। हाल के वर्षों में बुडापेस्ट और कीव के बीच संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। शिनहुआ समाचार एजेंसी के अनुसार, हंगरी ने रूस से अपनी ऊर्जा आपूर्ति के मुख्य मार्ग, ड्रुज्बा तेल पाइपलाइन पर यूक्रेन के हमलों की बार-बार आलोचना की है और यूक्रेन के ट्रांसकारपैथियन क्षेत्र में जातीय हंगरी अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर चिंता जताई है। साथ ही, हंगरी यूक्रेन के ईयू में शामिल होने के प्रोसेस का कड़ा विरोध करता है, क्योंकि उसे अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की गारंटी की जरूरत है और साथ ही यूक्रेन के ईयू में शामिल होने से ईयू के कृषि सब्सिडी सिस्टम पर नकारात्मक असर पड़ने की आशंका है। उच्च स्तरीय बातचीत तनावपूर्ण रही है, और दोनों पक्ष अक्सर सार्वजनिक बयानों में एक-दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं। इन विवादों के बावजूद, हंगरी ने फरवरी 2022 में सशस्त्र संघर्ष शुरू होने के बाद से यूक्रेन को मानवीय सहायता दी है, शरणार्थियों के लिए अपनी सीमाएं खोलीं और शरणार्थी बच्चों के लिए यूक्रेनी भाषा का स्कूल भी खोला। पहले जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि यूक्रेनी सेना ने देश के हवाई क्षेत्र के उल्लंघन की जानकारी दी है, यह काम शायद हंगरी के रिऑनाइसेंस ड्रोन ने किया है और प्रारंभिक आकलन से पता चलता है कि उड़ानों का लक्ष्य यूक्रेन के सीमावर्ती औद्योगिक क्षेत्र हो सकते हैं।

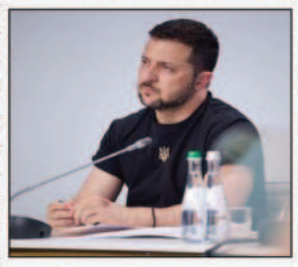

बांग्लादेश में शारदीय दुर्गा पूजा के दौरान अल्पसंख्यक हिंदूओं में डर

एजेंसी

ढाका। बांग्लादेश में शारदीय दुर्गा पूजा के आयोजन के संबंध में मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस, सेना प्रमुख वकर उज जमान और गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) जहांगीर आलम चौधरी सहित सरकार के सर्वोच्च अधिकारियों के आश्वासनों के बावजूद अल्पसंख्यक हिंदूओं में डर का माहौल है। देश में धार्मिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने वाले मानवाधिकार संगठन हिंदू-बौद्ध-ईसाई ओइक्या परिषद (एकता परिषद) की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में इस आशय का आरोप लगाते हुए कहा गया है कि इस मामले में यूनुस समेत देश के लगभग सभी उच्च अधिकारियों के बार-बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद भक्त त्योहार के दिनों में भी डरे हुए हैं। परिषद ने आरोप लगाया कि देशभर में दो सितंबर से 23 सितंबर तक पूजा मंडपों और मंदिरों पर हमलों और तोड़फोड़ की कम से कम नौ अलग-अलग घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें हमींदपुर, सादुल्लापुर, गैबांधा की घटना, पंचगढ़ सदर उपजिला के आयमा झालोई महारानी बांध क्षेत्र में काली मंदिर में मूर्ति तोड़े जाने की घटना, स्वरूपदाह पालपारा में कुशिया स्थित रक्षाकाली मंदिर में कार्तिक और सरस्वती की मूर्तियों में तोड़ फोड़, नेत्रोकोना के सदर उपजिला स्थित कंडुलिया कालीबाड़ी पूजा मंडप में दो मूर्तियों को तोड़े जाने की घटना, गाजीपुर शहर के काशिमपुर श्मशान मंदिर में तैयार हो रही पाँच-छह मूर्तियों को तोड़ा जाना।

शीर्ष अमेरिकी सैन्य अधिकारियों को अगले हफ्ते वर्जीनिया पहुंचने का आदेश

एजेंसी

वाशिंगटन। अमेरिकी के शीर्ष सैन्य अधिकारियों को अगले हफ्ते वर्जीनिया पहुंचने का आदेश दिया गया है। रक्षा सचिव (अब युद्ध सचिव) पीट हेगसेथ ने यह आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई अफसर नहीं पहुंचता तो उसे इसका पर्याप्त और समुचित कारण बताना होगा। मंगलवार को होने वाले इस सैन्य जमावड़े को शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। देश के कमांडर-इन-चीफ डोनाल्ड ट्रंप इस दौरान मौजूद रहेंगे या नहीं, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। आदेश में सिर्फ जनरल और एडमिरल स्तर के अधिकारियों को ही बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, यह बैठक इसलिए आहूत की गई है कि प्रशासन रक्षा विभाग के पुनर्निर्माण को युद्ध विभाग के रूप में वर्णित कर सके और सैन्य कर्मियों के लिए नए मानकों की रूपरेखा तैयार की जा सके। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया, यह राष्ट्रपति के अधीन नई सेना की वर्तमान स्थिति का शक्ति प्रदर्शन है। इस आयोजन

की रूप-रेखा से परिचित एक रक्षा अधिकारी ने कहा, हेगसेथ के लिए यह घोड़ों को अस्तबल में लाने और उन्हें चाबुक से दुरुस्त करने की कोशिश है। बताया गया है कि आयोजन से पहले या कार्यक्रम स्थल पर हेगसेथ का रिकॉर्डेड भाषण जारी किया जा सकता है। एक अधिकारी ने बताया कि व्हाइट हाउस इसे और भी व्यापक बनाने की योजना बना रहा है। ऐसी बड़ी बैठक का मूल विचार हेगसेथ का ही है। जिन सैकड़ों जनरलों और फ्लैग ऑफिसर्स को आमंत्रित किया गया है, उन्हें यह भी नहीं बताया गया कि सब कुछ छोड़कर वर्जीनिया जाने का आदेश क्यों दिया गया । द साल्ट लेक ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, यूटा नेशनल गार्ड के जनरलों को हेगसेथ की शीर्ष सैन्य अधिकारियों की इस आकस्मिक बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। यह बैठक मंगलवार को वर्जीनिया के क्वांटिको स्थित मरीन कॉर्प्स बेस (हिल एयर फ़ोर्स बेस) पर होनी है। एक ही स्थान पर इतने वरिष्ठ सैन्य अफसरों की इस दुर्लभ बैठक ने सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ा दी हैं, इसमें विदेशों में युद्धक तैनाती से अमेरिका लौट रहे जनरलों के भी शामिल होने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि यूटा नेशनल गार्ड में कम से कम चार जनरल हैं। इनमें राज्य के शीर्ष सैन्य प्रमुख, एडजुटेंट जनरल, एक सहायक, और सेना व वायु सेना नेशनल गार्ड इकाइयों के जनरल अधिकारी शामिल हैं। पेंटागन के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने यूटा के सैन्य प्रमुखों को बैठक में आमंत्रित न करने की वजह पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

ट्रंप के टैरिफ बम के कारण शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, निवेशकों के 6.60 लाख करोड़ स्वाहा

एजेंसी

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ के नए ऐलान, आईटी सेक्टर के शेयरों में आई गिरावट, कमजोर ग्लोबल संकेतों और विदेशी निवेशकों की बिकवाली के कारण घरेलू शेयर बाजार आज लगातार छठे दिन गिरावट का शिकार हो गया। आज के कारोबार की शुरुआत भी कमजोरी के साथ हुई थी। बाजार खुलने के बाद कुछ देर के लिए खरीदारों ने लिवाली का जोर बनाने की भी कोशिश की, लेकिन इसके बाद पूरे दिन बाजार में बिकवाली का दबाव बना रहा। दिनभर के कारोबार के बाद सेंसेक्स 0.90 प्रतिशत और निफ्टी 0.95 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए। आज दिनभर के कारोबार के दौरान बीएसई के सभी सेक्टोरल इंडेक्स में लगातार बिकवाली का दबाव बना रहा। फार्मास्यूटिकल, आईटी, मेटल और एनर्जी सेक्टर के शेयरों में आज सबसे अधिक बिकवाली होती रही। इसके साथ ही पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, बैंकिंग, ऑयल एंड गैस, ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, एफएमसीजी और टेक इंडेक्स भी गिरावट के साथ बंद हुए। ब्रॉडर मार्केट में भी आज लगातार बिकवाली होती रही, जिसके कारण बीएसई का मिडकैप इंडेक्स 1.96 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ। इसी तरह स्मॉलकैप इंडेक्स ने 2.05 प्रतिशत की कमजोरी के साथ आज के कारोबार का अंत किया।

मुंबई एयरपोर्ट पर सीमा शुल्क विभाग की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों के मादक पदार्थ और विदेशी मुद्रा बरामद

मुंबई। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (सीएसएमआई), मुंबई पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने 21 से 24 सितंबर के बीच की ड्यूटी के दौरान कई बड़ी कार्रवाइयां करते हुए करोड़ों रुपए के मादक पदार्थ, विदेशी मुद्रा और सोना बरामद किया है। अधिकारियों ने विभिन्न मामलों में दो यात्रियों को गिरफ्तार भी किया है। दूसरे मामले में विशिष्ट सूचना पर कार्रवाई करते हुए सीमा शुल्क अधिकारियों ने मुंबई से दुबई जा रही फ्लाइट नंबर ईके-509 के एक यात्री को रोका। यात्री के हैंडबैग बैग से 7.11 लाख भारतीय रुपए के बराबर विदेशी मुद्रा बरामद की। मुद्रा को छुपाकर ले जाया जा रहा था। तीसरे मामले में इसी फ्लाइट (ईके-509) से दुबई जा रहे एक अन्य यात्री को भी रोककर जांच की गई। यात्री के हैंड बैग से विदेशी मुद्रा बरामद हुई, जिसकी भारतीय रुपए में कीमत ?49.38 लाख बताई गई। चौथे मामले में प्रोफाइलिंग के आधार पर बैंकॉक से फ्लाइट नंबर एसक्यू-424 से आए एक यात्री को जांच के लिए रोका गया। इस दौरान यात्री के ट्रॉली बैग से 18.400 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 18.40 करोड़ रुपए आंकी गई। यात्री को एनडीपीएस एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

कोल इंडिया ने गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के लिए 1.03 लाख के त्योहारी इनाम की घोषणा की

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनियों ने त्योहारों से ठीक पहले अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) ने अपने गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के लिए 1.03 लाख रुपये के प्रदर्शन-आधारित पुरस्कार (पीएलआर) देने की घोषणा की। कोयला मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के कोयला उपक्रमों ने अपने गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के लिए 1,03,000 रुपये के प्रदर्शन-आधारित पुरस्कार की घोषणा की है। कोयला उद्योग के लिए संयुक्त द्विपक्षीय समिति की मानकीकरण समिति की 25 सितंबर को हुई छठी बैठक के बाद इस प्रोत्साहन पुरस्कार देने की घोषणा की गई। पीएलआर से कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों के लगभग 2.1 लाख गैर-कार्यकारी संवर्ग के कर्मचारियों और एससीसीएल के करीब 38,000 गैर-कार्यकारी संवर्ग के कर्मचारियों को फायदा होगा। यह राशि उपस्थिति के आधार पर आनुपातिक आधार पर जमा की जाएगी। इस प्रदर्शन-आधारित पुरस्कार का कुल वित्तीय भार सीआईएल के लिए 2153.82 करोड़ रुपये और एससीसीएल के लिए 380 करोड़ रुपये होगा।

योगी कैबिनेट में 22 प्रस्ताव मंजूर, कृषि खरीद से लेकर औद्योगिक निवेश तक हुए बड़े निर्णय

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति प्रदान की गई। बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री योगेंद्र उपाध्याय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने कैबिनेट के फैसलों की विस्तृत जानकारी साझा की। खन्ना ने बताया कि सभी प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी मिली है, जो राज्य के आर्थिक, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में नई दिशा प्रदान करेंगे। कृषि क्षेत्र को राहत देने वाले फैसलों ने किसानों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी है। खरीफ वर्ष 2025-26 के लिए मूल्य संवर्धन योजना के अंतर्गत धान क्रय नीति की घोषणा की गई है। इसके तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक धान की खरीद की जाएगी। गत वर्ष कॉमन धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2300 रुपये प्रति क्विंटल था, जो इस वर्ष बढ़ाकर 2369 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसी प्रकार, ग्रेड ए धान के लिए पिछले वर्ष 2330 रुपये प्रति क्विंटल के मुकाबले इस वर्ष 2389 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

रूसी कच्चे तेल पर कोई प्रतिबंध नहीं: हरदीप पुरी

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि रूस से कच्चे तेल की खरीद पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आपूर्ति बाधित होने पर दुनिया को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। हरदीप पुरी ने यहां संवददाताओं से बातचीत के दौरान ईरान और वेनेजुएला के मामलों का हवाला देते हुए कहा कि भारत ने वैश्विक समुदाय के एक जिम्?मेदार सदस्य के रूप में हमेशा अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का पालन किया है। पेट्रोलियम मंत्री ने अमेरिका के भारत पर 25 फीसदी शुल्क के अलावा रूस से कच्चा तेल एवं हथियार खरीदने पर 25 फीसदी का अतिरिक्त शुल्क लगाने के संदर्भ में यह बात कही। अमेरिका और भारत के बीच व्यापार नीतियों पर जारी महत्वपूर्ण वार्ता के बीच संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पुरी ने कहा कि रूस हर दिन करीब एक करोड़ बैरल के साथ विश्व स्तर पर कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। उन्होंने आगाह किया कि यदि आपूर्ति बाधित होती है, तो विश्व को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

हरदीप पुरी ने कहा, ''ऊर्जा एक

ऐसी चीज है जिसके बिना आप नहीं रह सकतेज। उन्होंने कहा कि अगर आप दूसरे सबसे बड़े उत्पादक को हटा देंगे, तो आपको खपत में कटौती करनी होगी। इसके परिणाम बेहद गंभीर होंगे।'' पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि रूस से कच्?चे तेल खरीद की मूल्य सीमाएं तय की गई हैं, जब भी ऐसी कोई बात होती है, तो वह भारतीय कंपनियों से कम कीमतों पर तेल खरीदने का अनुरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि तुर्किये, जापान और यूरोपीय संघ सहित कई देश रूस से तेल खरीदते हैं।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तेल की मांग एवं आपूर्ति के बीच 'व्यापक संतुलन' जरूरी है। उन्हें उम्मीद है कि आगे भी कच्चे तेल का मूल्य 65-68 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के बीच बना रहेगा। पुरी ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां स्वतंत्र रूप से यह निर्णय लेती हैं कि वे रिफाइनिंग के लिए किस स्रोत से कच्चा तेल खरीदेंगी। इन कंपनियों के पास पेशेवर प्रबंधन और निदेशक मंडल भी हैं। उन्होंने कहा कि भारत की विकास गाथा दुनियाभर में गूंज रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में भारत का ऊर्जा क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन से प्रेरित होकर, इस यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। पुरी ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनियां भारत के विकास की एक मजबूज रीढ़ हैं, इनके पास एक बड़ा परिसंपत्ति और उपभोक्ता आधार है और ये भारत के कुछ सबसे बड़े ब्रांडों के मालिक होने के कारण एक मजबूत प्रतिस्पर्धी स्थिति में हैं।

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 39.6 करोड़ डॉलर घटकर 702.57 अरब डॉलर पर

एजेंसी

नई दिल्ली। विदेशी मुद्रा भंडार में तीन हफ्ते की बढ़त के बाद गिरावट दर्ज हुई है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 19 सितंबर को समाप्त हफ्ते में 39.6 करोड़ डॉलर घटकर 702.57 अरब डॉलर रह गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने आंकड़े जारी करके बताया कि 19 सितंबर को समाप्त हफ्ते में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 39.6 करोड़ डॉलर घटकर 702.57 अरब डॉलर रहा है। इससे पिछले हफ्ते देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 4.69 अरब डॉलर बढ़कर 702.97 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान मुद्रा भंडार का अहम घटक मानी जाने वाली विदेशी मुद्रा

आस्तियां 86.4 अरब डॉलर घटकर 586.15 अरब डॉलर रह गईं। हालांकि, देश का स्वर्ण भंडार 36 करोड़ डॉलर बढ़कर 92.77 अरब डॉलर हो गया। रिजर्व बैंक के अनुसार इस दौरान विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 10.5 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.87 अरब डॉलर हो गया। आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष में भारत की आरक्षित भंडार 20 लाख डॉलर बढ़कर 4.76 अरब डॉलर पर पहुंच गया। देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार इससे पहले सितंबर, 2024 के अंत में बढ़कर अब तक के उच्चतम स्तर 704.88 अरब डॉलर पर पहुंच गया था।

ट्रंप के टैरिफ का भारतीय फार्मा कंपनियों पर दिखा असर, दवा कंपनियों के शेयरों में गिरावट

एजेंसी

नई दिल्ली। आयातित ब्रांडेड यानी पेटेंट वाली दवाओं पर लगाया गया 100 फीसदी अमेरिकी टैरिफ एक अक्टूबर से प्रभावी होगा, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के बाद अधिकांश दवा कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई है। भारतीय शेयर बाजार में अधिकांश दवा कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई है। बीएसई हेल्थकेयर सूचकांक 2.14 फीसदी नीचे आ गया। ऐसे में आइए जानते हैं फार्मा पर टैरिफ का भारतीय कंपनियों पर कितना असर होगा और किन कंपनियों की मुश्किलें ज्यादा बढ़ सकती है। भारतीय फार्मा कंपनियों के लिए अमेरिका बड़ा बाजार है। वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में भारत से संयुक?त राज?य अमेरिका को 3.7 अरब डॉलर का फार्मा निर्यात हुआ था। फार्मा एक्सपोर्ट में अमेरिका हिस्सा 40 फीसदी है। फार्मा एक्सपर्ट का 100 फीसदी टैरिफ लगाने पर कहना है कि इससे भारत पर सीमित असर होगा। क?योंकि, जेनेरिक दवाओं पर अभी टैरिफ नहीं लगा है। जेनेरिक दवा कंपनियों के लिए पॉलिसी रिस्क है। भारतीय दवाएं यूएस के मुकाबले 35-40 फीसदी सस्ती हैं। भारतीय

कंपनियों की अमेरिका में सस्ती हेलकेयर देने में अहम भूमिका है। अमेरिकी टैरिफ से सन फार्मा पर ज्यादा असर होगा। कंपनी के स्पेशलिटी पोर्टफोलियो बिक्री में अमेरिका का हिस्सा 19 फीसदी है। यूएस टैरिफ से सन फार्मा के मार्जिन और सेल्स पर असर पड़ सकता है। अमेरिका में सिप्ला, डॉ रेड्डीज लैब्स और ल्यूपिन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इन कंपनियों पर टैरिफ का बहुत ही कम असर होगा। कंपनियों की कमाई में अमेरिकी कारोबार के योगदान की बात करें, तो ग्लैंड फार्मा की आय में अमेरिकी बिक्री की हिस्सेदारी 50 फीसदी है। अरबिंदो फार्मा की कमाई में अमेरिकी कारोबार की हिस्सेदारी 48 फीसदी है।घटी दरों पर सामान न दे दुकानदार, तो 8800001915 पर शिकायत या 1915 पर करें कॉल

डॉ. रेड्डीज लैब्स की इनकम में अमेरिकी निर्यात की हिस्सेदारी 47 फीसदी है। जाइडस लाइफ की इनकम में अमेरिकी कारोबार की हिस्सेदारी 46 फीसदी है। ल्यूपिन का कमाई में अमेरिका का योगदान 37 फीसदी है। इसी तरह सन फार्मा के रेवेन्यू में अमेरिका का योगदान 32 फीसदी है। इसके अलावा सिप्ला की इनकम में अमेरिका में होने वाली बिक्री की हिस्सेदार 29 फीसदी है।

केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही में बाजार से 6.77 लाख करोड़ रुपये जुटाएगी

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही में 6.77 लाख करोड़ रुपये बाजार से उधार लेने की योजना बनाई है। इसमें सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (एसजीआरबी) जारी करके 10 हजार करोड़ रुपये जुटाए जायेंगे। वित्त मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा कि बजट 2025-26 में केंद्र सरकार ने 14.82 लाख करोड़ रुपये की सकल उधारी का अनुमान जताया था। हालांकि, चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में सरकार की उधारी 5 हजार करोड़ रुपये कम हुई है। इसके अलावा दूसरी छमाही (अक्टूबर-मार्च) के अनुमान में भी 5,000 करोड़ रुपये की कटौती की गई है। इससे वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल उधारी का अनुमान 10 हजार करोड़ रुपये कम हो गया है। इस तरह से चालू वित्त वर्ष के लिए कुल उधारी अब 14.72 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। यह बजट अनुमान से 10 हजार करोड़ रुपये कम होगा।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि दूसरी छमाही की कुल 6.77 लाख करोड़ रुपये ही उधार लिए गए। मंत्रालय ने कहा कि सरकार दूसरी छमाही में उधारी की योजना को 22 साप्ताहिक नीलामी के जरिए छह मार्च 2026 तक पूरा करेगी।मंत्रालय के आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर ने

रुपये की उधारी में से 10 हजार करोड़ रुपये सरकारी हरित बॉन्ड के जरिये जुटाने की योजना है। सरकार ने पहली छमाही में आठ लाख करोड़ रुपये उधार लेने की योजना बनाई थी, जिसमें से 7.95 लाख करोड़ कहा कि कुल सकल उधारी अब 14.72 लाख करोड़ रुपये है, जो प्रारंभिक अनुमान से थोड़ा कम है। उन्होंने कहा कि सरकार राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने के प्रति प्रतिबद्ध है।

रुपया मामूली गिरावट के साथ बंद, यूरो और ब्रिटिश पौंड की तुलना में उछली भारतीय मुद्रा

एजेंसी

नई दिल्ली। फार्मास्यूटिकल सेक्टर पर भी अमेरिकी टैरिफ का बोझ लादने से बने नकारात्मक माहौल के कारण रुपया आज डॉलर की तुलना में मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। हालांकि, रुपये ने ज्यादातर दूसरी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं की तुलना में आज के कारोबार में मजबूती दिखाई। भारतीय मुद्रा आज डॉलर की तुलना में सिर्फ 3 पैसे फिसल कर 88.71 (अनंतिम) के स्तर पर बंद हुई। इसके पहले पिछले कारोबारी दिन गुरुवार को भारतीय मुद्रा 88.68 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुई थी।

रुपये ने आज के कारोबार की शुरुआत भी गिरावट के साथ ही की थी। इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भारतीय मुद्रा ने आज सुबह डॉलर के मुकाबले सिर्फ 1 पैसे की कमजोरी के साथ 88.69 रुपये के स्तर से कारोबार की शुरुआत की थी। आज का कारोबार शुरू होने के बाद कुछ देर के लिए रुपया मामूली रिकवरी करके 88.66 के स्तर तक भी पहुंचा, लेकिन इसके बाद बाजार

में बने नकारात्मक माहौल के कारण रुपया गिरकर 88.73 के स्तर तक पहुंच गया। पूरे दिन के कारोबार के बाद डॉलर की तुलना में रुपये ने 3 पैसे की कमजोरी के साथ 88.71 के स्तर पर आज के कारोबार का अंत किया। मुद्रा बाजार के आज के कारोबार में डॉलर की बात छोड़ दें तो रुपये ने ज्यादातर दूसरी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं के मुकाबले मजबूत प्रदर्शन किया। आज के कारोबार के बाद ब्रिटिश पौंड (जीबीपी) की तुलना में रुपया 80.89 पैसे की बढ़त के साथ 118.45 (अनंतिम) के स्तर पर पहुंच गया। इसी तरह यूरो की तुलना में रुपया आज 55.04 पैसे की मजबूती के साथ 103.59 (अनंतिम) के स्तर पर पहुंच कर बंद हुआ। टीएनवी फाइनेंशियल सर्विसेज के सीईओ तारकेश्वर नाथ वैष्णव का कहना है कि बाजार फिलहाल 1 अक्टूबर को आरबीआई द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं, जब मौद्रिक नीति समिति गिरते रुपये और व्यापार शुल्कों की अनिश्चितताओं के बीच अपने ब्याज दरों के फैसले की घोषणा करेगी। अभी यही कहा जा सकता है कि निवेशक और कारोबारी पूरी तरह से सतर्क मुद्रा में हैं, क्योंकि बाजार के सेंटिमेंट्स फिलहाल विदेशी पूंजी के प्रवाह, वैश्विक जोखिम का माहौल और भारत और अमेरिका के बीच नीतिगत मुद्दों में लगातार हो रहे बदलावों से जुड़ी है। ऐसे में फिलहाल कुछ दिन तक मुद्रा बाजार के साथ ही शेयर बाजार और कमोडिटी मार्केट में भी बड़ा जोखिम लेने से बचने की कोशिश करना चाहिए।

ई-पैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज का आईपीओ अंतिम दिन 3.07 गुना हुआ सब्सक्राइब

एजेंसी

नई दिल्ली। ई-पैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) बोली लगाने के अंतिम दिन 3.07 गुना अभिदान मिला (सब्सक्राइब) हुआ। स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम को 5.42 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुई हैं, जबकि प्रस्तावित शेयरों की संख्या 1.76 करोड़ थी। इस निर्गम को 3.07 गुना अभिदान प्राप्त हुआ। कंपनी ने एंकर निवेशकों से 151.2 करोड़ रुपये जुटाए हैं। आंकड़ों के अनुसार इस निर्गम को 1,76,70,103 इक्विटी शेयरों के मुकाबले 5,42,98,933 बोलियां

प्राप्त हुईं। इसमें योग्य संस्थागत निवेशकों और गैर-संस्थागत शेयरों को क्रमशः 5.10 गुना और 3.68 गुना अभिदान मिला है। वहीं, खुदरा शेयरों को 1.69 गुना अभिदान मिला। ये निर्गम बुधवार, 24 सितंबर को अभिदान के लिए खुला, जो आज 26 सितंबर, 2025 को बंद हो गया। ई-पैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के 504 करोड़ रुपये का ये आईपीओ 300 करोड़ रुपये की ताजा शेयर बिक्री और 204 करोड़ रुपये की बिक्री पेशकश का संयोजन है। इस इश्यू का मूल्य का दायरा 194-204 रुपये प्रति शेयर के बीच तय किया गया है। मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल लिमिटेड और मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड बुक-रनिंग लीड मैनेजर हैं और केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इस निर्गम का रजिस्ट्रार है।

सात्विक ग्रीन एनर्जी ने आईपीओ निवेशकों को किया निराश, पहले दिन ही 5 प्रतिशत से अधिक का नुकसान

एजेंसी

नई दिल्ली। सोलर मॉड्यूल्स बनाने वाली कंपनी सात्विक ग्रीन एनर्जी के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में कमजोर एंट्री करके अपने आईपीओ निवेशकों को निराश कर दिया। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 465 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बीएसई पर इसकी लिस्टिंग 5 रुपये के डिस्काउंट के साथ 460 रुपये के स्तर पर और एनएसई पर बिना किसी बदलाव के 465 रुपये के स्तर पर हुई। लिस्टिंग के बाद बिकवाली के दबाव में इस शेयर में और गिरावट आ गई। लगातार हो रही बिकवाली के कारण ये शेयर टूट कर 427.10 रुपये के स्तर तक आ गया। हालांकि बाद में लिवाली का सपोर्ट मिलने पर कंपनी के शेयर निचले स्तर से 12.60 रुपये की रिकवरी करके 439.70 रुपये के स्तर पर बंद हुए। इस तरह

पहले दिन के कारोबार में ही कंपनी के आईपीओ निवेशकों को 5.44 प्रतिशत का नुकसान हो गया।

सात्विक ग्रीन एनर्जी का 900 करोड़ रुपये का आईपीओ 19 से 23 सितंबर के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 6.93 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 11.41 गुना सब्सक्राइब हुआ था। वहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में 10.57 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इसी तरह रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 2.81 गुना और एंप्लॉयीज के लिए रिजर्व पोर्शन 5.59 गुना सब्सक्राइब हो सका था। इस आईपीओ के तहत 700 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए गए हैं। इसके अलावा 2 रुपये फेस वैल्यू वाले 43,01,075 शेयर ऑफर फॉर सेल विंडो के जरिये बेचे गए हैं। आईपीओ में नए शेयरों की बिक्री के जरिये जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी ओडिशा के गोपालपुर में 4 गीगावाट की सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने, पुराने कर्ज का बोझ कम करने और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों में करेगी।

अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने के लिए वार्ता जारी रखने का फैसला

एजेंसी

नई दिल्ली। पीयूष गोयल के नेतृत्व में अमेरिका गए प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार वार्ता (बीटीए) के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई है। इस दौरान दोनों पक्षों ने पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को जल्द ही अंतिम रूप देने के लिए बातचीत को जारी रखने का फैसला किया है। हालांकि, ये समझौता कब होगा इसकी जानकारी नहीं दी गई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि पीयूष गोयल के नेतृत्व में अमेरिका गया भारतीय प्रतिनिधिमंडल तीन दिनों के दौरे के बाद 24 सितंबर को स्वदेश लौट आया है। उच्चस्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते और निवेश संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से कई उपयोगी चर्चाएं कीं। मंत्रालय ने कहा कि इस चर्चा के दौरान दोनों पक्षों ने पारस्परिक रूप से लाभकारी प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार वार्ता (बीटीए) को जल्द ही अंतिम रूप देने के लिए बातचीत को जारी रखने का फैसला लिया है। मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने संयुक्त राज्य अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि, राजदूत जैमीसन ग्रीर और भारत में नियुक्त होने वाले अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर के साथ बैठकें कीं। द्विपक्षीय व्यापार मामलों पर अमरीकी सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों के अलावा प्रतिनिधिमंडल ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर अमेरिका स्थित प्रमुख व्यवसायों और निवेशकों के साथ चर्चा की।अमेरिका यात्रा के दौरान उच्चस्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने समझौते के विभिन्न पहलुओं पर अमेरिकी सरकार के साथ सकारात्मक बैठकें कीं। दोनों पक्षों ने समझौते की संभावित रूपरेखा पर विचारों का आदान-प्रदान किया और परस्पर लाभकारी व्यापार समझौते के शीघ्र होने के उद्देश्य से वार्ताओं को जारी रखने पर सहमित व्यक्त की। इसके अलावा इस दौरान व्यवसायों और निवेशकों के साथ हुई बैठकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली हैं। व्यापारिक नेतृत?व ने भारत की विकास गाथा में विश्वास जताया और भारत में अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को तेज करने की इच्छा व्यक्त की।

ईएसआईसी योजना से जुलाई महीने में जुड़े 20.36 लाख नए कर्मचारी

एजेंसी

नई दिल्ली। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की ईएसआई योजना के तहत जुलाई में कम से कम 20.36 लाख नए कर्मचारी जुड़े हैं, जो जून महीने में नामांकित कुल 19.37 लाख नए कर्मचारियों की तुलना में 4.86 फीसदी अधिक है।श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने जारी एक बयान में बताया कि जुलाई में 20.36 लाख नए पंजीकरणों में 48.37 फीसदी 25 वर्ष से कम आयु के युवा हैं। ईएसआईसी की ओर से जारी की गई पेरोल आंकड़ों के अनुसार जुलाई, 2025 तक 31,146 नए प्रतिष्ठानों को ईएसआई योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा दायरे में लाया गया है, जिससे अधिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। मंत्रालय के मुताबिक ईएसआई योजना के तहत जोड़े गए नए कर्मचारियों में 25 वर्ष तक की आयु वर्ग की भागीदारी 48 फीसदी से अधिक है। आंकड़ों के मुताबिक जुलाई महीने में जोड़े गए 20.36 लाख कर्मचारियों में से 9.85 लाख कर्मचारी 25 वर्ष तक की आयु वर्ग के हैं, जो कुल पंजीकरण का लगभग 48.37 फीसदी हिस्सा है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ओर से जारी पेरोल आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में शामिल कुल 20,36,008 कर्मचारियों में से महिला सदस्यों का पंजीकरण 4.33 लाख था। इसके अलावा जुलाई में ईएसआईसी स्कीम के तहत कुल 88 ट्रांसजेंडरों का भी पंजीकरण किया गया है।

पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के अंतर्गत पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 27 लाख से अधिक किसानों के खातों में गुरुवार को 21वीं किस्त के रूप में 540 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की। कृषि भवन में आयोजित वर्चुअल समारोह में कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय संकट की इस घड़ी में आपदा प्रभावित राज्यों के साथ मजबूती से खड़ा है। जिन नागरिकों के मकान टूट हो गए हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में आवास उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, मनरेगा में 150 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड हो या बाकी राज्य, इस संकट की घड़ी में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय उनके साथ खड़ा है। किसान के लिए चाहे बीज का

सवाल हो, पंजाब को रेपसीड और सरसों के बीज का आवंटन 32 करोड़ रु. का किया गया है। क्लस्टर रिमोंटेशन के तहत अतिरिक्त आवंटन भी करेंगे। गेहूं के बीज के लिए भी लगभग 74 करोड़ रु. अलग से दिए जाएंगे। जिन लोगों के मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, पीएम आवास योजना में उन्हें मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में 1 लाख 20 हजार रुपए के अलावा टॉयलेट की राशि अलग और 90-95 दिन की मनरेगा की राशि भी दी जाएगी। वहां के मजदूर भाई-बहनों को अगर रोजगार की जरूरत होगी तो मनरेगा में 100 दिन सालभर में रोजगार दिया जाता है, जिसे इन बाढ़ पीड़ित राज्यों में बढ़ाकर 150 दिन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पैकेज की घोषणा की है और उसी का एक हिस्सा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि समय पूर्व किसानों के खाते में डालना, ताकि उसका उपयोग प्राकृतिक आपदा से पीड़ित किसान खेती या अन्य कामों के लिए कर सकें। पंजाब के लगभग 11 लाख 10 हजार किसानों को करीब 222 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश के 8 लाख से ज्यादा किसानों को 160 करोड़ रुपये से अधिक तथा उत्तराखंड के लगभग 7.90 लाख किसानों को करीब 158 करोड़ रुपये की राशि पीएम-किसान की किस्त के रूप में उनके खातों में हस्तांतरित की गई हैं। इस राशि को मिलाकर पीएम-किसान योजना के अंतर्गत इन तीनों राज्यों के किसानों को अभी तक कुल 13,626 करोड़ रु. दिए जा चुके हैं। इस अवसर पर कृषि भवन में केंद्रीय कृषि सचिव डा. देवेश चतुर्वेदी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे, वहीं तीनों राज्यों के कृषि मंत्री और उच्चाधिकारी वर्चुअल जुड़े थे।

अवेज दरबार के साथ खड़ी

गौहर खान

बसीर अली के खिलाफ किया कड़ा वार

रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के घर में एक बार फिर से बड़ा ड्रामा देखने को मिला है। शो के ताजा एपिसोड में घर के कंटेस्टेंट बसीर अली ने अवेज दरबार पर धोखाधड़ी और अन्य गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद अवेज भावुक होकर फूट-फूटकर रो पड़े। इस ड्रामाई स्थिति के बाद बाहर उनकी भाभी और मशहूर अभिनेत्री गौहर खान ने खुलकर उनका समर्थन किया है और बसीर अली के व्यवहार की कड़ी आलोचना की है।

बिग बॉस के टास्क ने खोले राज़

यह पूरा घटनाक्रम बिग बॉस के एक टास्क के दौरान शुरू हुआ, जब कंटेस्टेंट्स के सामने कुछ क्लिप्स दिखाई, जिनमें बसीर अली और अमल मलिक अवेज दरबार के बारे में चर्चा करते नजर आए। क्लिप में बसीर ने अवेज पर गंभीर आरोप लगाए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। अवेज ने इन आरोपों को पूरी तरह से नकारते हुए कहा कि ये झूठ हैं और उन्होंने अपने रिश्ते को लेकर पूरी ईमानदारी से काम किया है। उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में उन्होंने

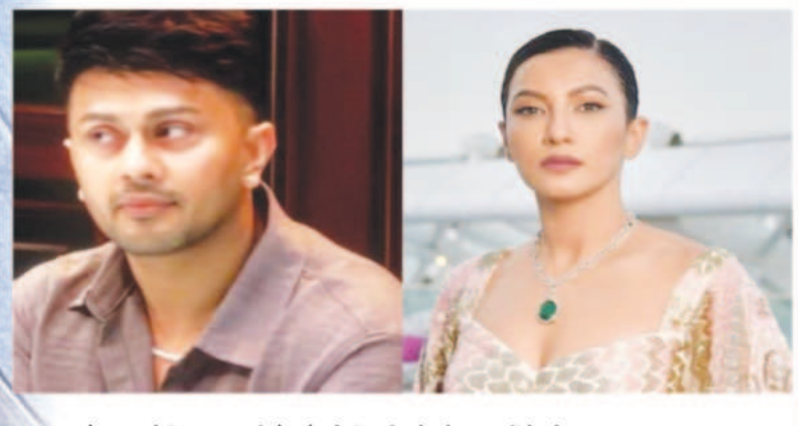

नगमा के साथ डेटिंग शुरू की है और वे किसी को धोखा नहीं दे रहे।

गौहर खान का बयान

इस पूरे विवाद को देख कर गौहर खान ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक क्लिप साझा करते हुए लिखा, बसीर को चुप रहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अवेज को टारगेट किया। हीरो बनने के चक्कर में इंसान कितनी बुरी हरकतें कर सकता है! गौहर के इस बयान ने फैंस के बीच हलचल मचा दी और कई लोगों ने भी बसीर की आलोचना करनी शुरू कर दी।

घर में बढ़ा तनाव

एपिसोड में जब अवेज आरोपों से टूट गए और भावुक होकर रोने लगे, तो घर के अन्य सदस्य गौरव, अभिषेक, प्रणित और अशनूर ने उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की। अभिषेक ने उन्हें यह सलाह दी कि वह आरोपों से हताश न हों बल्कि मजबूती से सामना करें। हालांकि अवेज ने शुरुआत में बसीर का सामना करने का मन बनाया था, लेकिन बाद में गुस्से को कंट्रोल करते हुए स्थिति को संभालने का फैसला किया।

बसीर ने मांगी माफी

घटना के बाद बसीर अली ने अवेज, नगमा और उनके परिवार से माफी मांगते हुए झगड़े को खत्म करने की कोशिश की। हालांकि विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन यह स्पष्ट है कि इस टास्क ने सभी के लिए भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण पल खड़े कर दिए हैं।

बर्थडे पार्टी में बदल गई थी तब्बू की किस्मत, सुपरस्टार ने ऑफर की थी फिल्म

बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा तब्बू ने अपनी बड़ी बहन और एक्ट्रेस फराह नाज की राह पर चलते हुए फिल्मी दुनिया में छोटी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था और फिर उन्होंने फराह से भी ज्यादा नाम कमाया. फराह तो बॉलीवुड से जल्दी दूर हो गई थीं. लेकिन, तब्बू आज भी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. लेकिन, क्या आप ये जानते हैं कि एक्ट्रेस को अपनी पहली फिल्म कैसे मिली थी? उन्हें उनकी डेब्यू फिल्म देवानंद जैसे दिग्गज कलाकार ने ऑफर की थी.तब्बू ने बतौर लीड एक्ट्रेस अपना डेब्यू दक्षिण भारतीय सिनेमा से किया था. इसके बाद वो बॉलीवुड में आई थीं. हालांकि बतौर लीड एक्ट्रेस काम करने से पहले तब्बू ने बॉलीवुड में बाल कलाकार के रूप में भी काम किया था. उन्हें ये मौका देवानंद ने दिया था. तब्बू ने बताया था कि एक बर्थडे पार्टी में जाने के बाद उनकी किस्मत ने करवट ली थी.

देव आनंद की बेटी के रोल से किया डेब्यू

तब्बू ने एक शो पर बताया था कि एक बार वो एक बर्थडे पार्टी में गई थीं, जहां उनकी मां की सहेली सुषमा आंटी भी थीं. सुषमा, देव साहब की साली थीं. बर्थडे पार्टी में सुषमा ने तब्बू को देखा था और उस वक्त देव साहब को अपनी फिल्म हम 'नौजवान' के लिए एक चाइल्ड आर्टिस्ट की जरूरत थी.तब्बू ने आगे कहा था कि एक दिन शबाना आंटी (एक्ट्रेस शबाना आजमी) ने उनसे मुलाकात की और बताया कि देव साहब की एक फिल्म है, जिसमें तुम्हें काम करना चाहिए. पहले तो तब्बू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, लेकिन फिर वो इसके लिए राजी हो गईं. तब्बू ने नौजवान फिल्म में देव साहब की बेटी का किरदार निभाया था. उस वक्त एक्ट्रेस की उम्र 14 साल थी.

देव साहब ने ही दिया था स्क्रीन नेम तब्बू

तब्बू का पूरा नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी है. लेकिन, ये नाम काफी बड़ा था और देव साहब चाहते थे कि स्क्रीन पर अभिनेत्री का नाम कुछ अलग हटकर दिखे. बताया जाता है कि बचपन में एक्ट्रेस को सभी तब्बू कहकर बुलाते थे और देव साहब को भी ये नाम पसंद आया.

दिलजीत दोसांझ से नवाजुद्दीन सिद्दीकी तक, एमी अवाईस में चमके ये इंडियन सितारे

इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स में भारतीय एक्टर्स और क्रिएटर्स अपनी छाप छोड़ रहे हैं. महत्वपूर्ण नॉमिनेशन से लेकर ऐतिहासिक जीत तक, इंडियन सितीरों, कॉमेडियन्स और क्रिएटर्स ने देश की कहानी और कलात्मकता को दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाया है. एमी अवॉर्ड्स में भारत को रिप्रेजेंट करने वाले कुछ खास नामों पर एक नज़र डालते हैं.एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ ने बेस्ट एक्टर कैटेगरी में अपने पहले नॉमिनेशन के साथ इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में एंट्री की है. उन्हें इम्तियाज़ अली की बनाई गई बायोपिक अमर सिंह चमकीला में पंजाबी एक्टर अमर सिंह चमकीला की भूमिका निभाने के लिए नॉमिनेट किा गया है. इस खास मौके पर उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, यह सब इम्तियाज़ अली सर की वजह से है. वहीं डायरेक्टर ने दिलजीत की तारीफ की.

वीर दास

कॉमेडियन-एक्टर वीर दास ने 2023 में वीर दास: लैंडिंग के लिए बेस्ट कॉमेडी स्पेशल का एमी अवॉर्ड जीतकर इतिहास रच दिया था. यह अचीवमेंट ग्लोबल लेवल पर भारतीय स्टैंड-अप के लिए एक बड़ा कदम था. वीर इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स की होस्टिंग करने वाले पहले भारतीय भी बने. सोशल मीडिया पर उन्होंने लोगों का आभार व्यक्त करते हुए लिखा, एक भारतीय एमी होस्ट, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद. मैं इस साल एमी की होस्टिंग करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं.

अर्जुन माथुर

साल 2020 में अर्जुन माथुर ने भारत को बेस्ट एक्टर कैटेगरी में पहला इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स में नॉमिनेशन दिलवाया था. मेड इन हेवन में समलैंगिक विवाह योजनाकार करण मेहरा की उनकी भूमिका प्रेम, पहचान और एक्सप्टेंस के इर्द-गिर्द घूमती नजर आई. उनकी एक्टिंग ने कहानी सुनाने के तरीके और रिप्रेजेंटेशन को एक अलग ही लेवल पर पहुंचाया.

नवाजुद्दीन सिद्दीकी

नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सीरियस मेन में उनके काम के लिए एमी अवॉर्ड्स में नॉमिनेट किया गया था. उन्होंने एक ऐसे पिता की भूमिका निभाई थी, जो अपने बेटे के टैलेंट का दिखावा करके अपने परिवार में समृद्धि लाना चाहता है. दिग्गज एक्टर के अभिनय ने इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में भारत की बढ़ती उपस्थिति में योगदान दिया.

शेफाली शाह

शेफाली शाह को 2023 में दिल्ली क्राइम: सीज़न 2 में डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी की भूमिका के लिए नॉमिनेट किया गया था, जिसमें उन्होंने बड़ी सहजता से अधिकार और कमज़ोरी का परिचय दिया था.

1050 करोड़ का मालिक है

अनुष्का शर्मा

का पति, पूरी दुनिया में बजता है नाम का डंका

आज बात बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में, जिसने साल 2008 में शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार संग अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था. फिर उन्होंने आमिर खान, अक्षय कुमार, सलमान खान और रणबीर कपूर जैसे दिग्गजों संग भी काम किया. इस एक्ट्रेस के साथ ही उनके पति भी देश-

दुनिया में एक बड़ा नाम बना चुके हैं. यहां हम आपसे बात कर रहे हैं अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की.

अनुष्का शर्मा ने फिल्म 'रब ने बना दी जोड़ी' से बॉलीवुड में अपने कदम रखे थे. ये फिल्म सुपरहिट निकली थी. इसके बाद एक्ट्रेस ने हिंदी सिनेमा में 'पीके', 'सुल्तान', 'संजू', बैंड बाजा बारात', 'ए दिल है मुश्किल' और 'जब तक है जान' है जैसी बेहतरीन फिल्मों से खुद को साबित किया. जबकि विराट कोहली भी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. क्रिकेट के इस सुपरस्टार को पूरी दुनिया जानती है और वो नाम के साथ ही खूब पैसा कमाने में भी कामयाब रहे हैं.

अनुष्का शर्मा की नेटवर्थ

विराट कोहली की नेटवर्थ से पहले अनुष्का शर्मा की संपत्ति पर एक नजर डाल लेते हैं. बॉलीवुड में अनुष्का ने अपने करीब 17 साल के करियर में खूब पैसा कमाया है. अनुष्का शर्मा एक फिल्म के लिए 10 से 15 करोड़ रुपये के बीच चार्ज करती हैं. जबकि ब्रांड एंडोर्समेंट से एक्ट्रेस तीन करोड़ रुपये तक कमाती हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुष्का के पास 255 करोड़ रुपये की नेटवर्थ है.

विराट कोहली की नेटवर्थ

विराट कोहली साल 2008 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं. तीनों ही फॉर्मेट में उन्होंने अपनी खास और बड़ी पहचान बनाई है. टी-20ड्ड से विराट 2024 में और टेस्ट से मई 2025 में रिटायरमेंट लें चुके हैं. जबकि विराट वनडे क्रिकेट खेलते रहेंगे. विराट दुनिया के सबसे रईस क्रिकेटर्स में से एक हैं.

सरस्वती बाल मंदिर में गणित-विज्ञान मेला एवं संस्कृति महोत्सव का भव्य आयोजन

दिव्य दिल्ली: दिल्ली के पश्चिम विहार स्थित सरस्वती बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान, समर्थ शिक्षा समिति के तत्वावधान में गणित, विज्ञान मेला एवं संस्कृति महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में विद्यालय की प्रधानाचार्या ममता शर्मा के साथ महेंद्र कुमार, सुनील जालान, रेनू अग्रवाल और संजीव कृष्ण शर्मा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे डॉ. सतीश चंद्र चेतल, जिन्होंने बच्चों को अपने संबोधन में मेहनत,

लगन और विज्ञान के प्रति रुचि बनाए रखने की प्रेरणा दी। महोत्सव में नार्थ जोन के विभिन्न विद्यालयों से आए प्रतिभावान विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

बच्चों ने अपने-अपने प्रोजेक्ट्स और मॉडल्स के माध्यम से गणित एवं विज्ञान के कठिन विषयों को सरल और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया। वहीं संस्कृति महोत्सव के अंतर्गत लोकनृत्य प्रस्तुतियों ने वातावरण को जीवंत बना दिया। रंग-बिरंगे परिधानों में सजे बच्चों ने जब मंच पर अपनी प्रस्तुतियाँ दीं, तो उपस्थित दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका उत्साह बढ़ाया।महोत्सव के अंत में निर्णायकों ने सभी विद्यार्थियों के कार्यों को देखा और उनकी सराहना करते हुए उन्हें उभरते सितारे करार दिया।

निर्णायकों का कहना था कि इन बच्चों के प्रयास न केवल उनकी रचनात्मकता और प्रतिभा का प्रमाण हैं, बल्कि देश के उज्जवल भविष्य की झलक भी हैं। यह आयोजन बच्चों में विज्ञान एवं गणित के प्रति जिज्ञासा जगाने, संस्कृति से जोड़ने और सामूहिक प्रतिभा को सामने लाने का एक सशक्त मंच साबित हुआ।

भारत बायोएनर्जी और टेक एक्सपो के दूसरे संस्करण को संबोधित करते नितिन गडकरी

मनीषा

दिव्य दिल्ली : जैव ऊर्जा एवं स्वच्छ तकनीकों पर आधारित इंडिया बायोएनर्जी एंड टेक एक्सपो का दूसरा संस्करण 24 से 26 सितंबर 2025 तक दिल्ली के यशोभूमि, द्वारका में आयोजित किया गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया है।केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन को संबोधित किया इस वर्ष एक्सपो का विषय ह्यट्रांजिशन टू नेट जीरोः नीड टू स्केल अप बायो-एनर्जी इनिशिएटिव्सह्न है, जो जलवायु परिवर्तन की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हरित ऊर्जा समाधानों पर भारत के बढ़ते फोकस को दशार्या

है। इस कार्यक्रम में उद्योग जगत के अग्रणी, नीति निमार्ता, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हो रहे हैं।एक्सपो में जैव ऊर्जा और संबद्ध क्षेत्रों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी), इथेनॉल, बायो-डीजल, अपशिष्ट-से-ऊर्जा, जैव-गतिशीलता, सतत विमानन ईंधन (एसएएफ), और बायोमास पेलेट जैसी प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सम्मेलन में जैव ऊर्जा क्षेत्र में नवीनतम रुझानों, नीतिगत सुधारों और तकनीकी प्रगति पर चर्चा होगी। इसमें देश और विदेश के 200 से अधिक वक्ता और 1000 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे।बता दे कि यह एक्सपो भारत की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा को आगे बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्थिरता लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु जैव ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करेगा। इसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में जैव ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करना है।

दिल्ली के चंदर विहार से महिला लापता, परिजनों ने लगाया अपहरण का आरोप

शिवानी कौर बमराह

दिव्य दिल्ली। दिल्ली के चंदर विहार इलाके से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। स्थानीय निवासी सतनाम सिंह का आरोप है कि उनकी पत्नी परमजीत कौर 31 मई 2025 की शाम को गुरुद्वारे जाने के लिए घर से निकली थीं, लेकिन वह वहां पहुंचीं ही नहीं। सतनाम सिंह का कहना है कि रास्ते से ही पंजाब के रहने वाले एक व्यक्ति इंद्रपाल सिंह बैन्स ने उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया। इस घटना के बाद से परमजीत कौर का कोई सुराग नहीं मिला है। सतनाम सिंह का आरोप है कि जब उन्होंने अपनी पत्नी से संपर्क करने की कोशिश की तो इंद्रपाल सिंह बैंस ने उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी। परिजनों का दावा है कि घटना के कुछ समय बाद उनकी बेटी की स्कूल टीचर के फोन पर परमजीत कौर का कॉल आया, जिसमें उन्होंने रोते हुए कहा झ्र ह्लमैं खतरे में हूं, मुझे यहां से बचा लो।ह्व इसके बाद से उनका मोबाइल भी बंद है और परिवार उनसे संपर्क नहीं कर पा रहा। सतनाम सिंह का कहना है कि उनकी दो छोटी बेटियां हैं और वह पत्नी को ढूंढने के लिए लगातार गुहार लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि मामले की गंभीरता के बावजूद स्थानीय पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही। इसी कारण उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और न्याय की मांग की है।

अश्वगंधा राष्ट्रीय जनजागरूकता अभियान का सफल आयोजन किया

दिव्य दिल्ली : राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के सहयोग से एवं च. ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक कॉलेज के साथ मिलकर प्रतिष्ठा संस्था द्वारा अश्वगंधा राष्ट्रीय जनजागरूकता अभियान का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों, विद्यार्थियों और समाज में अश्वगंधा की औषधीय, स्वास्थ्यवर्धक एवं आर्थिक महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना था।कार्यक्रम की शुरूआत दीप प्रज्वलन और भगवान धन्वंतरि वंदना से हुई। इसके पश्चात प्रतिष्ठा संस्था की अध्यक्ष सुश्री सोहिनी रोहिल्ला ने संस्था के उद्देश्यों और गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि "अश्वगंधा केवल स्वास्थ्य का आधार नहीं, बल्कि समाज के लिए समृद्धि और आत्मनिर्भरता का माध्यम भी है। इसके माध्यम से स्वास्थ्य और संपदा दोनों को सशक्त करना आवश्यक है।

आज अश्वगंधा की बढ़ती बाजार मांग किसानों और युवाओं के लिए नए अवसर खोल रही है।"विशेष अतिथि प्रो. (डॉ.) एम. बी. गौर ने संस्था का धन्यवाद करते हुए कहा कि "इस राष्ट्रीय जागरूकता अभियान में भाग लेकर मुझे प्रसन्नता हुई। हमें अपने देश को आयुर्वेद की ओर बढ़ाने और स्वास्थ्य व समृद्धि के लिए प्रेरित करना चाहिए।"संस्था के ट्रस्टी श्री विनोद नागर ने कहा कि "वैश्विक स्तर पर अश्वगंधा की माँग लगातार बढ़ रही है। यदि किसानों को उचित मार्गदर्शन मिले तो वे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डॉ. सुभाष साहू (निदेशक एवं प्राचार्य, च. ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक कॉलेज) ने कहा कि "अश्वगंधा का महत्व केवल चिकित्सा तक सीमित नहीं है। इसका सही उपयोग शिक्षा, शोध और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी नई संभावनाएँ खोलता है।"डॉ. भारत भोयर (विभागाध्यक्ष, द्रव्यगुण विभाग) ने कहा कि "अश्वगंधा की खेती और इसके उत्पादन के सही तरीके अपनाने से किसानों को स्थायी आय और स्वास्थ्य लाभ दोनों मिल सकते हैं।"श्री कैलाश (डश्ड, उजवा) ने अपने संबोधन में कहा कि "अश्वगंधा की खेती से किसानों की आय में स्थायी वृद्धि हो सकती है। इसके सही उत्पादन और विपणन तकनीकों से किसानों को लाभ सुनिश्चित किया जा सकता है।" उन्होंने यह भी कहा कि "किसानों को चाहिए कि वे बाजार की मांग को समझते हुए गुणवत्ता और प्रमाणन पर ध्यान दें, ताकि उनका उत्पाद खरीदारों तक उचित मूल्य पर पहुंचे। संस्था के सचिव श्री गिरीश शर्मा ने कहा कि "अश्वगंधा की खेती फार्म टू सॉइल' की अवधारणा को सशक्त बनाती है। किसानों को चाहिए कि वे इसकी खेती अपनाकर प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद को बढ़ावा दें।"ट्रस्टी श्री मुकेश कुमार ने कहा कि "अश्वगंधा केवल औषधीय पौधा नहीं बल्कि किसानों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का साधन है। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे।"डॉ. मोनिका शर्मा (अतिरिक्त निदेशक शैक्षणिक) ने कहा कि "अश्वगंधा के माध्यम से युवाओं और किसानों को ज्ञान, स्वास्थ्य और बाजार तक पहुँच के अवसर प्रदान करना संभव है।"

कार्यक्रम का संचालन डॉ. मोनिका शर्मा द्वारा किया गया। किसानों ने अपने प्रश्न रखे कि वे अपने उत्पाद को उचित मूल्य पर खरीदारों तक कैसे पहुँचा सकते हैं। विशेषज्ञों ने इस पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस अवसर पर पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई, विजेताओं को पुरस्कार और सभी प्रतिभागियों को भागीदारी एवं प्रशंसा प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। समापन से पूर्व पैनल चर्चा भी हुई, जिसमें औषधीय पौधों की खेती और संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया।

अंत में प्रतिभागियों को अश्वगंधा पौधों का वितरण किया गया और सामूहिक फोटोग्राफ एवं भोजन के साथ कार्यक्रम का सफल समापन हुआ।प्रतिष्ठा संस्था का मानना है कि इस प्रकार की पहलें आयुर्वेद एवं औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देंगी और भारत को स्वस्थ एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में सहायक सिद्ध होंगी।

ज्वाला हेड़ी आरडब्ल्यूए में नई जीएसटी दरों पर खुशी की लहर, व्यापारियों ने किया स्वागत

शिवानी कौर बमराह

दिव्य दिल्ली। दिल्ली के ज्वाला हेड़ी स्थित सामुदायिक भवन में ज्वाला हेड़ी आर.डब्ल्यू.ए. द्वारा भारत सरकार की ओर से घोषित नई जीएसटी दरों को लेकर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली। कार्यक्रम की अध्यक्षता ज्वाला हेड़ी आर.डब्ल्यू.ए. के प्रधान रविंद्र यादव ने की। मुख्य अतिथि के रूप में शकूरबस्ती विधानसभा से विधायक करनैल सिंह उपस्थित रहे, जिनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर ज्वाला हेड़ी मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारी, व्यापारी और

दुकानदार भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। सभी ने केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों को कम करने के फैसले का समर्थन करते हुए इसे व्यापारियों और आम जनता के लिए राहत भरा कदम बताया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों का सम्मानित किया गया और स्थानीय व्यापारियों ने एक स्वर में कहा कि यह निर्णय अर्थव्यवस्था को गति देगा और बाजारों में नई ऊर्जा का संचार करेगा।

पूनम पांडे की जगह मेजर शालू वर्मा निभाएंगी मंदोदरी की भूमिका

नई दिल्ली। लालकिला मैदान में आयोजित होने वाली विश्व प्रसिद्ध लव कुश रामलीला में इस बार एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अभिनेत्री पूनम पांडे की जगह अब मेजर शालू वर्मा मंदोदरी का किरदार निभाएंगी।

रामलीला समिति के अध्यक्ष अर्जुन कुमार और महासचिव सुभाष गोयल ने बताया कि पूनम पांडे ने समिति के आमंत्रण पर मंदोदरी की भूमिका निभाने के लिए सहमति दी थी, लेकिन उनके नाम की घोषणा के बाद विभिन्न संस्थानों और समाज के वर्गों से आपत्तियां सामने आईं। समिति का मानना है कि इससे रामलीला के मूल उद्देश्य–प्रभु श्रीराम का संदेश समाज

तक पहुँचाना–में बाधा उत्पन्न हो सकती थी। गहन विचार-विमर्श के बाद समिति ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि इस बार मंदोदरी की भूमिका मेजर शालू वर्मा को दी जाए। अर्जुन कुमार ने कहा, इस वर्ष हमारी रामलीला भी ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित है। इसी कारण हमने निर्णय लिया कि सेना से जुड़े कलाकारों को प्रमुख भूमिकाएं दी जाएं। मंदोदरी की भूमिका मेजर शालू वर्मा निभाएंगी। उनके अलावा भी सेना के चार-पाँच लोग रामलीला में महत्वपूर्ण किरदारों में नजर आएंगे। इस निर्णय को लेकर समिति और दर्शकों में उत्साह है, क्योंकि पहली बार रामलीला मंचन में सेना के अधिकारी इतने बड़े पैमाने पर भाग ले रहे हैं।

25 हजार का इनामिया औरंगजेब मुठभेड़ में घायल

बागपत। बागपत जिले की दोघट पुलिस ने गौ हत्या मामले में फरार चल रहे 25 हजारी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। बदमाश के पास से तमंचा कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। औरंगजेब पर गौतस्करी और गौ हत्याओं जैसे संगीन अपराध दर्ज हैं। दोघट थाना पुलिस व मिशन शक्ति की टीम ने दोघट थाने पर दर्ज मुकदमो के कुख्यात अपराधी औरंगजेब को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। औरंगजेब पर 25000 का इनाम है। शुक्रवार की रात औरंगजेब हथियारों के साथ किसी वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहा था। जिसकी भनक पुलिस को लग गयी। दोघट पुलिस ने उसको कन्नड़ से पालडी मार्ग पर ललकारा। जिसके बाद औरंगजेब ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में औरंगजेब के पैर पर गोली लगी और उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि औरंगजेब गौ तस्करी, गौ हत्याओं जैसे संगीन अपराधों में लिप्त है और काफी समय से फरार चल रहा था। औरंगजेब बागपत जिले के ही पालड़ी गांव का रहने वाला है इसके खिलाफ दोघट थाने पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोघट पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है।

अलग - अलग धर्म से उनके लोगों के लव पर ऑब्जेक्शन समझ से परे - अतहर जमाल लारी

वाराणसी। बहुजन समाज पार्टी के वाराणसी लोकसभा से प्रत्याशी और बेबाक विषय रखने वाले अतहर जमाल लारी ने कहा कि सबको अपने धर्म से लव करने का अधिकार है। इस पर किसी व्यक्ति को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अलग अलग धर्म से उनके लोगों के लव पर ऑब्जेक्शन समझ से परे है। कोई आई लव मोहम्मद कहे, कोई आई लव

महादेव कह दे या
आई लव क्राइस्ट, आई लव गुरु नानक, आई लव बुद्ध कहे, इस पर ऑब्जेक्शन सही नहीं है। अतहर जमाल लारी ने आगे कहा कि वाराणसी सहित प्रदेश में लव वाले पोस्टर के विरोध में जो कुछ हो रहा है, ये भी पूरी तरह से समझ के परे है। बरेली में हुई घटना के संबंध में अभी कुछ कहना ठीक नहीं है। यह जांच का विषय है, इसके बाद ही कुछ कहना ठीक होगा।

मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री ने अशोक सिंघल को किया नमन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अशोक सिंघल की जयंती पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आपका जीवन सनातन संस्कृति के संरक्षण और राष्ट्ररक्षा के संकल्प का अनुपम प्रतीक है। हम सभी आपके तप, त्याग और तेजस्विता को नमन करते हैं।

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट एक्स पर लिखा कि श्रद्धेय अशोक सिंघल ने अपना सम्पूर्ण जीवन भारत माता की सेवा और भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण के लिए समर्पित कर दिया। उनके नेतृत्व ने समाज को एक नई चेतना दी, करोड़ों लोगों में आत्मविश्वास जगाया और राष्ट्र को अपनी जड़ों से जुड़ने की प्रेरणा दी।

अशोक सिंघल ने श्री रामजन्मभूमि मंदिर आंदोलन को केवल एक संघर्ष नहीं, बल्कि राष्ट्र की अस्मिता का महायज्ञ बना दिया। उनकी वाणी में एक अटूट संकल्प था, कर्म में त्याग और दृष्टि में राष्ट्रहित सर्वोपरि था।भारत में सांस्कृतिक जागरण के प्रतीक परम

चार राजनीतिक दलों को नोटिस जारी, जवाब न देने पर होगी कार्रवाई

गौतम बुद्ध नगर। भारत निर्वाचन आयोग के आदेश पर गौतम बुद्ध नगर के चार राजनीतिक दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन दलों ने तीन वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखा जोखा और परिक्षित खाते की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। उन्होंने किसी चुनाव में भाग भी नहीं लिया है। गौतम बुद्ध नगर जनपद के प्रभारी सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने शनिवार को बताया कि जिले की भारतीय भाईचारा पार्टी, लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय भारतीय जन जन पार्टी व राष्ट्रीय जनता पार्टी को नोटिस जारी किया गया है। सभी दलों को जवाब देने के लिए समय सीमा दिया गया है। यदि समय पर इन्होंने जवाब नहीं दिया तो उनके पास इस विषय में कोई भी अभ्यावेदन नहीं है। ऐसे में पार्टी को पंजीकृत राजनीतिक दल की सूची से हटाए जाने के संबंध मे भारत निर्वाचन आयोग को पत्र भेजा जाएगा।

भविष्य निधि खाताधारकों के भुगतान को लेकर हुई बैठक

चित्रकूट ब्यूरोः महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रयागराज द्वारा सामान्य भविष्य निधि खाता धारकों के सुगमतापूर्वक भुगतान किये जाने के उद्देश्य से शुक्रवार को उप महालेखाकार विजय सिंह पंवार की अध्यक्षता में कलेक्टरेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने कोषागार का निरीक्षण किया तथा कार्यशाला में सामान्य भविष्य निधि एवं वित्त लेख के सम्बंध में अदालत का आयोजन किया गया। बताया कि जी.पी.एफ भुगतान की सभी प्रक्रियाएं आनलाइन कर दी गई है।

गोरखपुर में नीट की तैयारी कर रहे छात्र दीपक की हत्या में फरार जुबैर मुठभेड़ में मारा गया

रामपुर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में नीट की तैयारी कर रहे छात्र दीपक गुप्ता की हत्या के मामले में फरार चल रहे एक लाख रुपये का इनामी बदमाश मुठभेड़ में मारा गया। इस कार्रवाई में दो पुलिस कर्मी घायल हुए हैं। घटना की जानकारी पर पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल की।

एसपी ने बताया कि एनकाउंटर में मारे गए बदमाश की पहचान रामपुर के शहर कोतवाली मोहल्ला मर्दान खां का जुबैर उर्फ कालिया के रूप में हुई है। वह आठ साल से पशु तस्करी के धंधे में लिप्त था। बीते 15 सितंबर को जुबैर अपने साथियों के साथ गोरखपुर जिले के पिपराइच गांव में चोरी के इरादे से पशुओं को वाहनों में लाद रहा था।। इस दौरान लोगों की नींद खुल गई और तस्करों पकड़ने के लिए दौड़े। उनका पीछा कर रहे छात्र दीपक गुप्ता को तस्करों ने डीसीएम में पकड़कर बैठा लिया। गांव से कुछ दूर ले जाकर उसे फेक दिया था। सिर पर चोट लगने से छात्र की मौत हो गई थी। इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने पकड़े गए एक तस्कर को बहुत मारा। बीच बचाव करने आई पुलिसकर्मी भी ग्रामीणों के आक्रोश के शिकार हुए। इसमें कई लोग चोटिल हुए थे। मौके पर पहुंचकर पुलिस अधिकारियों ने मामले को संभाला था। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 12 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर भागे बदमाशों की तलाश कर रही थी। उनमें कुछ बदमाशों पर पर इनाम भी घोषित किया गया था। शुक्रवार रात गोरखपुर एसटीएफ और रामपुर पुलिस को जुबैर की लोकेशन रामपुर इलाके मे मिली थी।

Published, printed and owned by Rajesh.Chauhan, printed at Dinesh Sharma 19, DSIDC Sheds, Scheme 3, Okhla Phase-2 New Delhi -110020 and published at BG 6 305 B Paschim Vihar New Delhi --110063 Editor Rajesh.Chauhan. E mail ID-rajeshchauhan4569@gmail.com, Contact No. - 9873104569, RNI No.- DLHIN/25/A2321